वर्ष 12 • अंक 286 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शनिवार 18 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

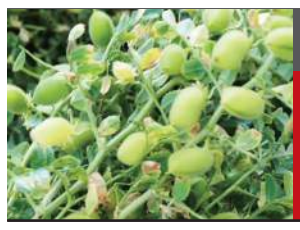

▶▶ पृष्ठ 6

चने की रिकॉर्ड बुआई से तेजी पर लगाम

अजय पीरामल ▶▶ पृष्ठ 2

पीरामल 95 करोड़ डॉलर में बेचेगी सहायक इकाई

डॉलर रु. 71.10 ▲ 20 पैसे | यूरो रु. 79.00 ▼ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 39809 ▲ 69 रुपये | सेंसेक्स 41945.40 ▲ 12.80 | निफ्टी 12352.30 ▼ 3.20 | निफ्टी फ्यूचर्स 12384.70 ▲ 32.30 | ब्रेंट क्रूड 65.00 डॉलर ▲ 0.20 डॉलर

एक नज़र

वित्त मंत्रालय ने बढ़ाया जीएसटी संग्रह का लक्ष्य

बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने जनवरी और फरवरी के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह का लक्ष्य मौजूदा 1.10 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.15 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसके साथ ही मार्च के लिए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य 1.25 लाख करोड़ रुपये पर बरकरार रखा गया है। मंत्रालय का मानना है कि डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट में धोखाधड़ी का पता लगाने पर विशेष ध्यान दिए जाने से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। पिछले साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये संग्रह का लक्ष्य रखा था। पृष्ठ 4

भूषण पावर के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ आरोप-पत्र दायर

प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपये के धनशोधन मामले में शुक्रवार को भूषण पावर ऐंड स्टील के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजय सिंघल और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। यह मामला कथित बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़ा है। आरोप-पत्र विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत के समक्ष दाखिल किया गया। सिंघल को मामले में पूछताछ के बाद धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत पिछले साल 22 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

जेट एयरवेज नीदरलैंड का कारोबार केएलएम को बेचेगी

जेट एयरवेज की योजना अपने नीदरलैंड के कारोबार को केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस को बेचने की है। जेट एयरवेज ने नकदी संकट के चलते पिछले साल अप्रैल में अपना परिचालन बंद कर दिया था। अभी कंपनी दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही है। शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि वर्तमान में कंपनी का कामकाज संभाल रहे ऋणशोधन समाधानकर्ता विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वह हितधारकों के लिए कंपनी के समाधान और अधिकतम मूल्य को सुनिश्चित करने की दिशा में ऐसा कर रहे हैं। पृष्ठ 2

चीन की जीडीपी दर तीन दशक के निचले स्तर पर

चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में 6.1 फीसदी रही जो पिछले 29 साल में सबसे निचला स्तर है। घरेलू मांग कमजोर रहने और अमेरिका के साथ 18 महीने तक चले व्यापार युद्ध के कारण दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।
चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने शुक्रवार को आधिकारिक आंकड़े जारी किए। चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में 6.1 फीसदी रही जो 1990 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन है। हालांकि यह 6 से 6.5 फीसदी के तय लक्ष्य के दायरे में रही है।

आज का सवाल

क्या आरआईएल के नतीजों से बाजार होगा निराश

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या एजीआर पर बढ़ेगी दूरसंचार फर्मों की मुश्किल?	हां	88.89%
	नहीं	11.11%

आंशिक भुगतान पर हो रहा विचार

24 जनवरी तक बकाया राशि का 20 फीसदी देने की संभावना तलाश रहीं दूरसंचार फर्में

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 17 जनवरी

दूरसंचार कंपनियां उच्चतम न्यायालय द्वारा तय समयसीमा से पहले अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के एक हिस्से का भुगतान करने की संभावना पर विचार कर रही हैं। यह राशि कुल एजीआर का 20 फीसदी तक हो सकती है। न्यायालय द्वारा तय समयसीमा 24 जनवरी को खत्म हो रही है।

न्यायालय ने पिछले साल 24 नवंबर को अपने आदेश में इन कंपनियों को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) का बकाया 90 दिन के भीतर चुकाने को कहा था। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने इस पर समीक्षा याचिका दायर की थी जिसे न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया। कंपनियों का कुल बकाया 147,000 करोड़ रुपये है।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक राजन मैथ्यू ने इस बात की पुष्टि की है कि बकाये के एक हिस्से के भुगतान के बारे में कंपनियों के बीच चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा, 'कुछ कंपनियां उच्चतम न्यायालय द्वारा तय समयसीमा से पहले अपने बकाये के एक हिस्से के भुगतान पर चर्चा कर रही हैं। यह राशि 20 फीसदी हो सकती है। साथ ही वे दूरसंचार विभाग से अनुरोध करना चाहती हैं कि उन्हें बाकी बकाया किस्तों में करने की अनुमति दी जाए।' सीओएआई ने इससे पहले सरकार को एक पत्र लिखकर कंपनियों को इस राशि के भुगतान के लिए दो साल तक बिल्कुल छूट के साथ दस साल का समय देने की मांग की थी। सीओएआई के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि लाइसेंस फीस का भुगतान और एसयूसी दूरसंचार विभाग और दूरसंचार कंपनियों के बीच एक अनुबंध है, इसलिए सरकार को किस्तों में भुगतान की योजना लानी चाहिए। मैथ्यू ने साथ ही कहा कि दूरसंचार कंपनियां अपने स्तर पर भी सरकार से अनुरोध कर सकती हैं और अंतिम फैसला होने के बाद सीओएआई भी दूरसंचार विभाग को एक पत्र भेज सकता है। उनका यह भी कहना है कि पहले दूरसंचार कंपनियां स्व-आकलन प्रक्रिया के तहत एजीआर बकाये की गणना करती हैं और फिर इसे दूरसंचार विभाग को भेजती हैं। विभाग फिर इसकी जांच पड़ताल करता है और इसे घटा या बढ़ा सकता है। दूरसंचार कंपनियों ने अपने एजीआर बकाये की गणना करके दूरसंचार विभाग को भेज दिया है।

अलबत्ता, कुछ कंपनियों के एजीआर बकाये की गणना और सरकार के हिसाब के बीच कुछ अनियिमितताएं हैं। उदाहरण के लिए वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के मामले में कंपनी ने अपनी समीक्षा याचिका में इसे 44,000 करोड़ रुपये बताया है जबकि दूरसंचार विभाग का दावा है कि कंपनी पर 55,000 करोड़ रुपये का बकाया है।

विश्लेषकों के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों की गणना के मुताबिक उन पर 99,000 करोड़ रुपये का बकाया है जबकि सरकारी दावे में यह राशि 110,000 करोड़ रुपये है। इन कंपनियों में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, रिलायंस जियो और टाटा की दूरसंचार कंपनियां तथा सरकारी क्षेत्र की बीएसएनएल और एमटीएनएल शामिल हैं। सरकार के लिए टेलीनॉर, एतिसलात और आरकॉम जैसी कंपनियों से वसूली करना मुश्किल है। आरकॉम का मामला आईबीसी में चल रहा है।

■ संबंधित खबरें : पृष्ठ 3

बाजार ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया

वोडाफोन आइडिया — रुपये में

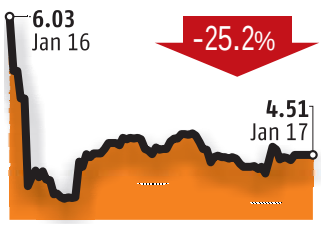

भारती एयरटेल — रुपये में

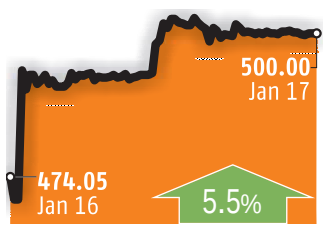

दूरसंचार कंपनियों के पास विकल्प

- एजीआर बकाये का सालाना बोझ कम करने के लिए किस्तों में भुगतान का अनुरोध
- बकाये के प्रभाव को खत्म करने के लिए लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क घटाने की मांग
- संशोधन याचिका दायर करने पर विचार
- भुगतान न करें, दिवालिया प्रक्रिया में जाएं

तेल पर फिसली, नए कारोबार से मिला दम

आरआईएल का लेखाजोखा

	2019-20 तीसरी तिमाही	2018-19 तीसरी तिमाही	वृद्धि फीसदी में
शुद्ध आय	1,68,858	1,71,300	-1.40
कर पूर्व मुनाफा	26,088	23,801	9.60
शुद्ध मुनाफा	11,640	10,251	13.50

आंकड़े करोड़ रुपये में, स्रोत : आरआईएल

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जनवरी

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के डिजिटल और खुदरा कारोबार ने पारंपरिक तेल एवं पेट्रोरसायन कारोबार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी बदौलत चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आरआईएल का कर पूर्व मुनाफा 3.6 फीसदी बढ़कर 14,962 करोड़ रुपये रहा। दूसरी ओर समूह के डिजिटल कारोबार का कर पूर्व मुनाफा 31.5 फीसदी बढ़कर 1,685 करोड़ रुपये रहा, वहीं रिलायंस रिटेल वेंचर का कर पूर्व मुनाफा 63 फीसदी बढ़कर 2,169 करोड़ रुपये रहा।

आरआईएल की आय भी निराश करने वाली रही। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आरआईएल की आय 1.4 फीसदी घटकर 1,68,858 करोड़ रुपये रही, जबकि रिलायंस जियो की आय 28 फीसदी और रिलायंस रिटेल की आय 27 फीसदी बढ़ी। कंपनी ने कहा कि आईयूसी शुल्क लागू करने की वजह से दिसंबर तिमाही के दौरान जियो को 2.23 करोड़ ग्राहक गंवाने पड़े। हालांकि कंपनी के ग्राहकों की कुल संख्या 37 करोड़ है और पिछली पांच तिमाहियों में उसने सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़े।

अक्टूबर-दिसंबर 2019 तिमाही में आरआईएल का शुद्ध मुनाफा 13.5 फीसदी बढ़कर 11,640 करोड़ रुपये रहा था। आरआईएल की आय में कमी मुख्य रूप से तेल-रसायन कारोबार की आय में 10.6 फीसदी गिरावट आने की वजह से हुई है। इसके साथ ही ब्रेंट क्रूड के दाम 6.6 फीसदी घटने की वजह से भी उसकी आय प्रभावित हुई। हालांकि उपभोक्ता कारोबार में तेजी से इस नुकसान की भरपाई करने में कंपनी सफल रही।

आरआईएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा, 'तीसरी तिमाही में हमारे ऊर्जा कारोबार के नतीजे वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी और ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव को परिलक्षित करते हैं। पेट्रोरसायन का मुनाफा कमजोर मार्जिन और नरम मांग की वजह से प्रभावित हुआ। हालांकि लागत कम करने के कारण रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार हुआ है।' तीसरी तिमाही में सकल रिफाइनिंग मार्जिन 9.2 डॉलर प्रति बैरल रहा, जो इससे पिछली तिमाही में 9.4 डॉलर था। पिछले वित्त वर्ष में इसी तिमाही में रिफाइनिंग मार्जिन 8.8 डॉलर प्रति बैरल रहा था।

सीलिंग से निजात चाहते हैं उद्यमी

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 17 जनवरी

- दुकान वाले कारोबारी सीलिंग की समस्या से चाहते हैं मुक्ति
- फैक्टरी वालों की मांग कारोबारी सुगमता के लिए हो एकल खिड़की मंजूरी तंत्र

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अगले कुछ दिन में घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। इनमें कारोबारियों के लिए भी चुनावी वादे किए जाएंगे। दिल्ली में दुकान वाले कारोबारी मुख्य रूप से इन दलों के घोषणा पत्र में सीलिंग की समस्या के समाधान का चुनावी वादा चाहते हैं, वहीं फैक्टरी वाले उद्यमी कारोबारी सुगमता के लिए एकल खिड़की मंजूरी तंत्र चाहते हैं। इनके अलावा कारोबारी अहम बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए विशेष फंड का वादा भी चाहते हैं।

दिल्ली फैक्टरी ओनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी ने बताया कि दिल्ली की कारोबारी सुगमता में स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में चुनावी घोषणा पत्र में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के उपाय होने चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी एकल खिड़की मंजूरी तंत्र है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उन गांवों में गोदामों को अनुमति दी जाए, जहां आग लगने की संभावना न हो। गैर पुष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में गैर प्रदूषित उद्योगों को ही चलाने की अनुमति मिले। घोषणा पत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के लिए विशेष फंड का वादा शामिल होना चाहिए। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री हेमंत गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली के कारोबारियों के लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या सीलिंग की मार है। इसलिए राजनीतिक दलों को अपने अपने घोषणा पत्र में इस समस्या के समाधान का वादा करना चाहिए। सीलिंग से निजात दिलाने के लिए माफी योजना की घोषणा हो और सील हो चुकी दुकानों को खोलने का वादा घोषणा पत्र में हो।

दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा ने बताया कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में दिल्ली के अहम बाजारों में सड़क, पानी, पार्किंग, शौचालय समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए फंड का प्रावधान होना चाहिए। कारोबारियों की राजनीतिक दलों से यह भी मांग है कि वे घोषणा पत्र में वैट के पुराने लंबित मामलों को निपटाने के लिए माफी योजना के वादे को शामिल करें।

ग्रेट वॉल मोटर्स खरीदेगी जीएम का तलेगांव संयंत्र

चीन की ग्रेट वॉल मोटर्स (जीडब्ल्यूएम) ने जनरल मोटर्स (जीएम) का तलेगांव निर्माण संयंत्र खरीदने के लिए समझौता किया है। शुक्रवार को एक संयुक्त बयान में कंपनियों ने यह जानकारी दी है। हालांकि इस सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार जीडब्ल्यूएम इस संयंत्र और मशीनरी के लिए जीएम को 2100 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। यह सौदा 2020 की दूसरी छमाही में पूरा हो जाने की संभावना है। इस सौदे से एसयूवी और पिक-अप की सबसे बड़ी निर्माताओं में से एक जीडब्ल्यूएम का भारतीय बाजार में प्रवेश सुनिश्चित हुआ है और इसके साथ ही भारत के घरेलू यात्री वाहन बाजार में अपनी कारों की बिक्री बंद करने के दो साल बाद जीएम अब भारत से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। जीडब्ल्यूएम के उपाध्यक्ष (वैश्विक रणनीति) लियू च्यांगशांग ने कहा कि यह सौदा भारत में प्रवेश और निवेश करने की कंपनी की योजना को ताकत प्रदान करेगा। पृष्ठ 2

बाजार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी टीसीएस

तीसरी तिमाही में आईटी फर्मों के नतीजे

	टीसीएस	इन्फोसिस	एससीएल टेक	विप्रो
राजस्व	39,854	23,092	18,135	15,470
सालाना वृद्धि	6.7	7.9	15.5	2.7
शुद्ध मुनाफा	8,118	4,457	3,037	2,463
सालाना वृद्धि	0.2	23.5	16.3	-3.2
परिचालन मार्जिन	25	21.9	20.2	18.4

नोट : राजस्व और मुनाफा करोड़ रुपये में, वृद्धि और परिचालन मार्जिन फीसदी में। विप्रो ने आईटी कारोबार का अलग से शुद्ध मुनाफा जारी नहीं किया है। *स्रोत : कंपनियां*

देवाशिष महापात्र और श्रीपाद ऑटे
बेंगलूरु/मुंबई, 17 जनवरी

देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का 31 दिसंबर, 2019 को खत्म तीसरी तिमाही में प्रदर्शन मिलाजुला रहा। आज जारी वित्तीय नतीजों के मुताबिक इस तिमाही में कंपनी की राजस्व वृद्धि पिछली आठ तिमाहियों में सबसे सुस्त रही लेकिन मुनाफे में सुधार आया।

बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं और बीमा (बीएफएसआई) और खुदरा जैसे अहम क्षेत्रों में सुस्ती देखने को मिली और कंपनी का कहना है कि इस वित्त वर्ष में दोहरे अंक में वृद्धि के लक्ष्य को हासिल कर पाना मुश्किल है। टाटा समूह की इस कंपनी में दिसंबर तिमाही में कर्मचारियों की संख्या में करीब 4,000 की कमी आई जिससे पता चलता है कि कंपनी में भर्ती प्रक्रिया भी धीमी पड़ी है।

दिसंबर तिमाही में टीसीएस का कर पूर्व मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 1.32 फीसदी गिरकर 10,569 करोड़ रुपये रहा। हालांकि दूसरी तिमाही के मुकाबले इसमें 0.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान कंपनी को 8,118 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 0.2 फीसदी और पिछली तिमाही के मुकाबले एक फीसदी अधिक है।

हालांकि दिसंबर तिमाही में टीसीएस का कुल राजस्व 39,854 करोड़ रुपये पहुंच गया जो पिछले वाल के मुकाबले 6.7 फीसदी अधिक है। यह पिछली तिमाही से 2.25 फीसदी ज्यादा है। तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी का डॉलर राजस्व 5.586 अरब डॉलर रहा जो पिछले साल के मुकाबले 6.4 फीसदी और पिछली तिमाही से 1.3 फीसदी अधिक है। स्थिर मुद्रा के लिहाज से टीसीएस का राजस्व पिछले साल के मुकाबले 6.8 फीसदी बढ़ा। इस तरह लगातार दूसरी तिमाही में कंपनी का राजस्व एकल अंक में बढ़ा है। तिमाही आधार पर यह बढ़ोतरी 0.3 फीसदी रही जो पिछले दो वर्षों में सबसे कम है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

बेजोस ने किया दस लाख नौकरियों का वादा

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 17 जनवरी

- एमेजॉन ने अगले पांच साल में देश में 10 लाख रोजगार सृजित करने की घोषणा की
- इससे एक दिन पहले एमएसएमई जैसे क्षेत्रों की मदद के लिए 1 अरब डॉलर निवेश का किया था ऐलान

दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर एमेजॉन ने आज कहा कि उसकी योजना तकनीक, बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर निवेश के जरिये वर्ष 2025 तक भारत में 10 लाख नौकरियां पैदा करने की है। सीधे और परोक्ष रूप से रोजगार के ये अवसर सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, कंटेंट निर्माण, खुदरा, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होंगे। कंपनी ने कहा कि यह रोजगार पिछले छह साल में उसके निवेश से सृजित हुए सात लाख से अधिक रोजगार से अलग होगा।

भारत की यात्रा पर आए एमेजॉन के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी जेफ बेजोस ने इससे पहले बुधवार को देश के कारोबारियों और एमएसएमई उद्यमों की मदद के लिए 1 अरब डॉलर निवेश करने और 2025 तक भारत से 10 अरब डॉलर के निर्यात की घोषणा की थी।

बेजोस ने कहा, 'हम भारत में अगले पांच साल में दस लाख नौकरियां पैदा करने के लिए निवेश कर रहे हैं। हमें, हमारे कर्मचारियों से अभूतपूर्व योगदान मिला है। हमने जुड़ने वाले छोटे कारोबारियों की असाधारण रचनात्मकता देखी है और ग्राहकों का अभूतपूर्व सहयोग भी हमें मिला है और अब आगे क्या होने वाला है, उसे लेकर हम रोमांचित हैं।' एमेजॉन भारत में अब तक 6.5 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जता चुकी है। रोजगार सृजन और कौशल विकास पहल सरकार की प्राथमिकता है और 2022 तक शहरी और ग्रामीण इलाकों में 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है। एमेजॉन ने कहा कि कंपनी की रोजगार सृजन और कारोबारियों तथा एमएसएमई के क्षेत्र में निवेश इस सामाजिक समावेशन का पूरक होगा और भारत के लोगों को रोजगार तथा उद्यमशीलता के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे।

2014 में अपनी शुरुआत के बाद से एमेजॉन भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या चार गुना तक बढ़ा ली है। पिछले साल उसने हैदराबाद में नया परिसर शुरू किया, जो अमेरिका के बाहर कंपनी का पहला पूर्ण-स्वामित्व वाला परिसर है। इसमें एक साथ 15,000 कर्मचारी काम कर सकते हैं।

कंपनी ने कहा कि वह सहेली, कारीगर और आई हैव स्पेस जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 5.50 लाख से अधिक कारोबारियों और एमएसएमई उद्यमों, स्थानीय दुकानदारों को भी अपना कारोबार का विस्तार करने के मौके उपलब्ध करा रही है।

एमेजॉन द्वारा 10 लाख नए रोजगार पैदा करने की योजना का घोषणा ऐसे समय में की गई है जब भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने भारी छूट को लेकर की गई शिकायतों पर एमेजॉन और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट की जांच के आदेश दिए हैं।

मेरा बयान गलत ढंग से पेश किया गया: गोयल

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि एमेजॉन के बारे में उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया। एमेजॉन पर कटाक्ष करते हुए गोयल ने गुरुवार को कहा था कि जब जेफ बेजोस भारत में अरबों डॉलर निवेश करने की बात कहते हैं तो उसका मुख्य मकसद कंपनी के घाटे की भरपाई होती है और ऐसा नहीं है कि वह भारत पर कोई अहसान कर रहे हैं। उन्होंने आज कहा, 'मैंने केवल यह कहा था कि देश में नियम-कानून के मुताबिक निवेश आना चाहिए।' खुदरा क्षेत्र में बड़े निवेश से छोटे व्यापारियों को नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके पास लाखों-करोड़ों रुपये नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'हम हर तरह के निवेश का स्वागत करते हैं। कानून के दायरे के बाहर कोई निवेश किया जाता है तो कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा।'

संबंधित खबर पृष्ठ 4

संक्षेप में

रिलायंस जियो का शुद्ध लाभ 62.5 फीसदी उछला

दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो का एकल आधार पर शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 62.5 फीसदी उछलकर 1,350 करोड़ रुपये हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान के अनुसार उसकी दूरसंचार इकाई जियो को इससे पूर्व वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 831 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी की परिचालन आय 28.3 फीसदी बढ़कर 13,968 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले 2018-19 की इसी तिमाही में 10,884 करोड़ रुपये थी। आरआईएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने एक बयान में कहा, जियो की बेमिसाल वृद्धि जारी है। मोबाइल कनेक्टिविटी सेवाओं के ग्राहकों का उत्साह बेजोड़ है। जियो अपनी वायरलाइन बुनियादी ढांचा, मनोरंजन और एफटीटीएक्स (फाइबर टू द एक्स-आप्टिकल फाइबर आधारित विभिन्न सेवाएं) सेवाओं के साथ बाजार को फिर से परिभाषित करने को प्रतिबद्ध है। रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में सालाना आधार पर 32.1 फीसदी बढ़कर 37 करोड़ पहुंच गई है। *भाषा*

कल्पतरु ने अलीपुरद्वार से सिलिगुड़ी लाइन को जोड़ा

कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अलीपुरद्वार से सिलिगुड़ी लाइन को ग्रिड के साथ जोड़ने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि यह काम उसके पूर्ण स्वामित्व वाली सकायक कंपनी अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) ने किया है। *भाषा*

पीरामल बेच रही सहायक कंपनी

पीरामल एंटरप्राइजेज 95 करोड़ डॉलर में डीआरजी को बेचने की तैयारी में

सोहिनी दास
मुंबई, 17 जनवरी

पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (पीईएल) ने आज कहा कि वह हेल्थकेयर इनसाइट्स ऐंड एनालिटिक्स कारोबार डिसिजन रिसोर्सेस ग्रुप (डीआरजी) की बिक्री नैसडेक में सूचीबद्ध क्लेरिवेट एनालिटिक्स को 95 करोड़ डॉलर में करेगी।

कंपनी ने कहा कि पीरामल के लिए यह रणनीतिक निवेश था और शेयरधारकों के लिए बेहतर कीमत देखते हुए उसे बेचने का फैसला लिया गया। बिक्री कीमत मोटे तौर पर डीआरजी की सालाना बिक्री का पांच गुना है।

पीरामल समूह के चेयरमैन अजय पीरामल ने कहा, पीरामल एंटरप्राइजेज में हमने शेयरधारकों के बेहतर हित में कदम उठाया है। हमें बिक्री का 5 गुना मूल्यांकन मिला है, जो मेरे विचार से पीरामल एंटरप्राइजेज के शेयरधारकों के लिए अच्छा मूल्यांकन है।

उन्होंने कहा कि पीरामल के देसी फॉर्म्युलेशन कारोबार की बिक्री ऐबट को करने के समय उसे आकर्षक मूल्यांकन हासिल हुआ था और बिक्री का फैसला लेने के लिए कंपनी प्रोत्साहित हुई। उन्होंने कहा, कुछ ऐसा ही हमने वोडाफोन के मामले में किया था। हमें लगता है कि अभी यह मूल्यांकन पीईएल के शेयरधारकों के लिए अच्छा है और उन्हें इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीरामल अपने अंतरराष्ट्रीय दवा कारोबार के लिए डीआरजी एनालिटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रही थी।

पीईएल ने साल 2012 में डीआरजी का अधिग्रहण करने पर 65 करोड़ डॉलर निवेश किया था, जिसमें से 26 करोड़ डॉलर इक्विटी के तौर पर दिए गए थे। कंपनी को रुपये के लिहाज से शुरुआती निवेश पर 2.3 गुना रकम वापस मिली है। सौदे की घोषणा के बाद शुक्रवार को पीरामल का शेयर एक्सचेंजों पर 5.5 फीसदी से ज्यादा उछल गया।

पीईएल ने कहा, जैसा कि पहले कहा गया था हम इस कंपनी में 10,000 करोड़ रुपये की इक्विटी लाने की राह पर हैं और तरजीही आवंटन के साथ हमने सीडीपीक्यू और राइट्स इश्यू के जरिए पूंजी जुटाई है। पिछले एक साल में कंपनी ने अल्पावधि की देनदारी चुकाने के लिए लंबी अवधि की 24,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई है। उन्होंने कहा कि इक्विटी जुटाने के पीईएल के मौजूदा कार्यक्रम के साथ यह सौदा न सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूती देगा बल्कि भविष्य में कंपनी के अहम मूल्यांकन के लिहाज से एक और कदम होगा। कंपनी अपने दवा कारोबार को सहायक कंपनियों में बांट रही है और दवा कारोबार में अतिरिक्त 20 फीसदी इक्विटी कैपिटल जुटाने पर काम कर रहे हैं। कंपनी खुद के दम पर और विलय-अधिग्रहण के जरिये बढ़त के मौके तलाशे जाएंगे।

क्लेरिवेट एनालिटिक्स 5 अरब डॉलर की कंपनी है, जो इनसाइट्स व एनालिटिक्स की अग्रणी कंपनी है और उसका राजस्व 1 अरब डॉलर, 4.300 कर्मचारी 42 देशों में हैं।

क्लेरिवेट एनालिटिक्स के कार्यकारी चेयरमैन और सीईओ जे स्टेड ने कहा, हमें लग रहा है कि यह अधिग्रहण मील का पत्थर है क्योंकि यह क्लेरिवेट लाइफ साइंसेज कारोबार के आकार को दोगुना करता है। इस अधिग्रहण से क्लेरिवेट 19 अरब डॉलर वाले लाइफ साइंसेज एनालिटिक्स बाजार में बेहतर स्थिति में स्थापित हो जाएगी, जो दो अंकों में बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है।

अजय पीरामल चतुर निवेशक हैं और सौदा करने के मामले में भी अच्छे हैं, जिससे उन्हें विभिन्न वर्षों में उच्च रिटर्न हासिल हुआ है। जब उन्होंने देसी फॉर्म्युलेशन कारोबार ऐबट को बेचा था तब कंपनी का मूल्यांकन उसकी बिक्री के नौ गुने से ज्यादा था। यह उस समय के बाजार के बेंचमार्क मूल्यांकन (रैनबैक्सी की बिक्री जापान की दायची को करने पर) के मुकाबले ज्यादा था।

परिसंपत्ति बिक्री

- इक्विटी पूंजी जुटाने की जारी योजना के साथ यह सौदा बैलेंस शीट को मजबूत बनाएगा, बिक्री कीमत मोटे तौर पर डीआरजी की सालाना बिक्री की पांच गुना है
- कंपनी की योजना फार्मा कारोबार में करीब 20 फीसदी इक्विटी जुटाने की है, जहां वह विलय-अधिग्रहण के मौके तलाश रही है
- अजय पीरामल अच्छे निवेशक रहे हैं क्योंकि वोडाफोन से निवेश निकासी, देसी दवा कारोबार की बिक्री से उनका भारी रिटर्न मिला है

ग्रेट वॉल मोटर्स खरीदेगी जीएम का तलेगांव संयंत्र

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 17 जनवरी

- जीडब्ल्यूएम लगभग 2100 करोड़ रुपये में जनरल मोटर्स का तालेगांव संयंत्र खरीदेगी
- यह सौदा 2020 की दूसरी छमाही तक पूरा हो जाने की संभावना है
- इस सौदे से जनरल मोटर्स के भारत से पूरी तरह निकलने का अनुमान है
- जनरल मोटर्स वर्ष के अंत तक भारत से निर्यात बरकरार रखेगी

चीन की ग्रेट वॉल मोटर्स (जीडब्ल्यूएम) ने जनरल मोटर्स (जीएम) का तलेगांव निर्माण संयंत्र खरीदने के लिए समझौता किया है। शुक्रवार को एक संयुक्त बयान में कंपनियों ने यह जानकारी दी है। हालांकि इस सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं किया गया है। अपुष्ट खबरों में कहा गया है कि जीडब्ल्यूएम इस संयंत्र और मशीनरी के लिए जीएम को 2100 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। यह सौदा 2020 की दूसरी छमाही में पूरा हो जाने की संभावना है।

इस सौदे से एसयूवी और पिक-अप की सबसे बड़ी निर्माताओं में से एक जीडब्ल्यूएम का भारतीय बाजार में प्रवेश सुनिश्चित हुआ है और इसके साथ ही भारत के घरेलू यात्री वाहन बाजार में अपनी कारों की बिक्री बंद करने के दो साल बाद जीएम अब भारत से पूरी तरह बाहर हो जाएगी।

जीडब्ल्यूएम के उपाध्यक्ष (वैश्विक रणनीति) लियू च्यांगशांग ने कहा कि यह सौदा भारत में प्रवेश और निवेश करने की कंपनी की योजना को ताकत प्रदान करेगा। लियू ने कहा, 'भारतीय बाजार में अच्छी संभावना, तेज आर्थिक वृद्धि और मजबूत निवेश परिवेश मौजूद है। भारतीय बाजार में प्रवेश करना ग्रेट वॉल मोटर्स की वैश्विक रणनीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'

जीडब्ल्यूएम ने कहा कि भारत में उसका निवेश परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोजगार अवसर पैदा करेगा, वाहन उद्योग में कौशल स्तर को बढ़ावा मिलेगा। मैं स्थानीय आपूर्ति चेन, आरऐंडडी और संबद्ध उद्योगों के विकास को बढ़ावा दूंगा और केंद्र तथा राज्य स्तरों पर सरकारों के खजाने में ज्यादा लाभ एवं करों में योगदान देने की कोशिश करूंगा।

चीन की इस कंपनी का कहना है कि वह आधिकारिक तौर पर ऑटो एक्सपो में अपने हैवल ब्रांड और जीडब्ल्यूएम ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) पेश करेगी और फिर भारतीय बाजार के बारे में अपनी योजना को आगे बढ़ाएगी।

जीएम कंपनी के उपाध्यक्ष (अंतरराष्ट्रीय परिचालन) जूलियन ब्लीसेट ने कहा, '2017 में निर्यात बाजारों को ध्यान में रखकर निर्माण के लिए तालेगांव संयंत्र पर ध्यान केंद्रित किए जाने के बाद से जीएम ने इस संयंत्र के बेहतर इस्तेमाल के लिए रणनीतिक विकल्प तलाशे हैं।' उन्होंने कहा कि तालेगांव में उत्पादन बंद करने का जीएम का निर्णय उसकी वैश्विक रणनीति पर आधारित है।

डेट्रॉयट की इस वाहन निर्माता ने कई वर्षों तक संघर्ष से जूझने के बाद 2017 में भारत से बाहर निकलने की घोषणा की थी। जहां उसने अपना हलोल संयंत्र एसएआईसी को बेच दिया था, वहीं तालेगांव में संयंत्र को अपने पाए बनाए रखा था और लैटिन अमेरिका तथा कुछ अन्य बाजारों के लिए कारों का निर्यात बरकरार रखा।

बाजार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी टीसीएस

पृष्ठ 1 का शेष...

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का राजस्व 8.4 फीसदी और अप्रैल-जून तिमाही में 11.4 फीसदी बढ़ा था।

टीसीएस के मुख्य कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक राजेश गोपीनाथन ने कहा, 'पिछले वित्त वर्ष में हमारी वृद्धि 11.4 फीसदी रही थी। इस बारे उसके करीब पहुंचने पहुंचने की उम्मीद नहीं है। अगर हम 8 फीसदी से बेहतर कर पाए तो मुझे खुशी होगी। यह उसी रेंज में है। संभावनाओं की रेंज ज्यादा व्यापक नहीं है। लेकिन हमें आगे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।'

स्थायी मुद्रा के लिहाज से टीसीएस की तिमाही वृद्धि आईटी क्षेत्र की सभी कंपनियों में सबसे कम रही। इन्फोसिस का राजस्व जहां तिमाही आधार पर एक फीसदी बढ़ा, वहीं विप्रो ने 1.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ष की। हालांकि टीसीएस का राजस्व आधार अपनी करीबी प्रतिद्वंद्वी कंपनी से दोगुना से भी अधिक है।गोपीनाथन ने कहा, 'तीसरी तिमाही हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रही क्योंकि साल की पहली छमाही के क्षेत्रवार रुझान इस तिमाही में भी जारी रहे। लेकिन हम अपने प्रदर्शन से खुश हैं।'

हालांकि मुद्रा विनिमय के लाभ और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए किए गए उपायों से अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान टीसीएस के परिचालन मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार आया।

क्रमिक आधार पर मार्जिन 100 आधार अंकों के सुधार के साथ 25 फीसदी पहुंच गया। कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी वी रामकृष्णन ने कहा कि उतारचढ़ाव वाले माहौल में हमारे मार्जिन में विस्तार टीसीएस के बिज़नेस मॉडल की ताकत को दिखाता है जो योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर और उच्च गुणवत्ता के राजस्व पर आधारित है।

कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 6 अरब डॉलर के बड़े सौदों पर हस्ताक्षर किए। इस तरह कंपनी इस वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में 18 अरब डॉलर से अधिक के सौदे कर चुकी है जो पिछले साल के मुकाबले 22 फीसदी अधिक है।

जेट एयरवेज का बोइंग विमान खरीदेगी केएलएम

अनीश फडणीस
मुंबई, 17 जनवरी

जेट एयरवेज पिछला विमान कर्ज चुकाने और नीदरलैंड में दिवालिया समाधान खर्च से संबंधित जरूरत पूरी करने के लिए अपने 6 बोइंग 777 विमानों में से एक की बिक्री केएलएम को कर रही है। दोनों एयरलाइंस के बीच इस संबंध में एक सशर्त समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर हुए थे और शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी जानकारी दी गई।

डच की एयरलाइन केएलएम इस समझौते के तहत जेट एयरवेज का एक बोइंग 777 खरीदेगी। इस सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बिक्री से जेट को लगभग 2.3 करोड़ डॉलर की रकम मिल सकती है। जेट एयरवेज ने पिछले साल अप्रैल में अपना परिचालन बंद कर दिया और उसे नीदरलैंड में परिसमापन प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। उसके एक बोइंग 777 विमान को स्थानीय अदालत के आदेश के बाद पिछले साल अप्रैल में एम्सटर्डम में जब्त कर लिया गया था। विमान की बिक्री से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल दिवालिया समाधान प्रक्रिया पर और अमेरिकी एग्जिम बैंक का ऋण चुकाने में किया जाएगा।

एक व्यक्ति ने कहा कि यह समझौता भारतीय ऋणदाताओं के लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे विमानों पर एग्जिम बैंक का नियंत्रण समाप्त करने में मदद मिलेगी। जेट एयरवेज फिलहाल दिवालिया समाधान प्रक्रिया के अधीन है। एयरलाइन के लिए प्रतिबद्ध खरीदार तलाशने की कोशिश अभी तक सफल नहीं हुई है और जिन कुछ कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, उन्होंने निवेश के संदर्भ में कुछ शर्तें रखी हैं। आरपी आशिष छाछरिया ने कहा है कि कायाकल्प और उसके शेयरधारकों की वैल्यू बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'यदि प्रस्तावित सौदा पूरा होता है तो यह सिर्फ कंपनी की कुछ व्यावसायिक गतिविधियों से संबद्ध होगा और इसका कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।'

सरकार ही दे सकती है राहत : बैंक

आरबीआई पहले ही कह चुका है कि बैंकों के लिए दूरसंचार क्षेत्र परेशानी का सबब बन सकता है

अभिजित लेले
मुंबई, 17 जनवरी

वोडाफोन आइडिया के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) संबंधी बकाये को लेकर उद्योग जगत में चिंता के बीच इस समूह में काफी निवेश कर चुके बैंकों का कहना है कि वे अब कुछ खास नहीं कर सकते। उनका कहना है कि डिफॉल्ट के मामले को छोड़कर दूरसंचार ऑपरेटरों के पुनर्भुगतान दायित्वों पर नए सिरे से काम करने की अब कोई गुंजाइश नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए कोई भी राहत पहले सरकार की ओर से आनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया समूह का कुल बकाया मार्च 2019 तक 1.25 लाख करोड़ रुपये हो चुका था। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार से कोई राहत न मिलने की स्थिति में सबसे अधिक झटका वोडाफोन आइडिया को लगेगा।

गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, बकाये भुगतान दायित्व को छोड़कर वोडाफोन आइडिया का कुल ऋण बोझ करीब 28,000 करोड़ रुपये का है। सितंबर 2019 तक उसका कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य परिसंपत्तियां 15,400 करोड़ रुपये थी जबकि उसका शुद्ध ऋण 13,000 करोड़ रुपये का था। हालांकि बैंकरों का कहना है कि ऋण मानक परिसंपत्ति है जिसका मतलब यह हुआ कि कंपनी ने पुनर्भुगतान में कभी चूक नहीं की है।

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा था कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए दूरसंचार क्षेत्र परेशानी का सबब बन सकता है। केंद्रीय बैंक ने इस क्षेत्र में निवेश के लिए मानक परिसंपत्ति प्रावधान को बढ़ा दिया था।

बैंकरों ने कहा कि केवल एक कंपनी के दबावग्रस्त होने से केंद्रीय बैंक अपने मानदंडों में बदलाव नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर, परिसंपत्ति मान्यता एवं प्रावधान मानदंड अन्य खातों की तरह ही रहेंगे।

एक निजी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा संभवत: दायर की जाने वाली उपचारात्मक याचिका पर सरकार अनुकूल जवाब देगी। हालांकि इससे देनदारी खत्म नहीं हो सकती है लेकिन हमारा मानना है कि सरकार भुगतान को सात साल के लिए टाल सकती है। इससे उनका बोझ कम होगा।'

करीब एक पखवाड़ा पहले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा था कि एजीआर जैसी दूरसंचार क्षेत्र की पिछली देनदारी संबंधी मुद्दे को निपटाना जरूरी है। कुमार ने कहा कि दूरसंचार एक प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र है जहां भारी निवेश की जरूरत होती है लेकिन दूरसंचार पर एजीआर मुद्दे का प्रभाव निश्चित तौर पर चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा तब तक चिंता बरकरार रहेगी क्योंकि इस क्षेत्र में बैंकों का काफी अधिक निवेश है।

दूरसंचार कंपनियों ने अपनी समस्याओं से निपटने के लिए शुल्क दरों में बढ़ोतरी की है और पिछले साल नवंबर में सरकार ने भी स्पेक्ट्रम बकाये के भुगतान के लिए उन्हें दो वर्षों का समय दिया था ताकि कुछ राहत मिल सके।

सरकार ने कहा था कि स्पेक्ट्रम नीलामी के किस्तों का भुगतान 2021-22 के बाद ही शुरू होगा। इससे दबावग्रस्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नकदी प्रवाह में सुधार होगा और इससे उन्हें वैधानिक देनदारी एवं बैंक ऋण पर ब्याज का भुगतान करने में मदद मिलेगी।

वोडाफोन आइडिया में निवेश बैंकिंग प्रणाली में मौजूद कुल गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का महज 2 फीसदी हिस्सा है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इतने बड़े डूबते ऋण से निवेशकों का भरोसा प्रभावित होगा और बैंक दूरसंचार कंपनियों में निवेश के जोखिम से बचने लगेंगे।

वोडाफोन आइडिया में सबसे अधिक निवेश करने वाले बैंकों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (आईडीएफबी), इंडसइंड बैंक और भारतीय स्टेट बैंक शामिल हैं। आईडीएफबी का शुद्ध निवेश करीब 11 फीसदी है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इंडसइंड बैंक के निवेश का एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार के पक्ष में गैर-फंड आधारित दायित्व से संबंधित है।

इस बीच, रेटिंग एजेंसियों ने भी दूरसंचार ऑपरेटरों की वित्तीय स्थिति और ऋण प्रोफाइल पर संभावित दबाव का उल्लेख किया है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कॉरपोरेट फाइनैंस) अनलिसा डि चियारा ने कहा कि यह एक ताजा झटका है लेकिन फैसला कोई आश्चर्यजनक नहीं है। भारती एयरटेल पहले ही प्रावधान कर चुकी है ताकि बहीखाते पर दबाव को दूर किया जा सके। फिर भी, उसके ऋण प्रोफाइल पर इसका उल्लेखनीय प्रभाव होगा।

गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार से कोई राहत न मिलने पर सबसे अधिक झटका वोडा-आइडिया को लगेगा

वोडाफोन-आइडिया में चुनिंदा बैंकों का निवेश

बैंक	वोडा-आइडिया में निवेश (करोड़ रुपये)	दूसरी तिमाही में निवेश (नेटवर्थ का प्रतिशत)
आईडीएफसी लि.	2,500	11
इंडसइंड बैंक	3,995	2.2
एसबीआई	11,200	04
आईसीआईसीआई बैंक	1,725	01
पंजाब नैशनल बैंक	1,027	01

वोडाफोन आइडिया अगर बंद हुई तो क्या होगा...

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 17 जनवरी

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का परिचालन बंद होने से दूरसंचार बाजार में दो निजी कंपनियों का वर्चस्व होगा जो न केवल ग्राहकों एवं रोजगार सृजन के लिहाज से बल्कि सरकार के लिए राजस्व के लिहाज से भी गंभीर परिस्थिति होगी। विश्लेषकों का कहना है कि इससे देश में निवेश की संभावनाएं तलाश रहीं विदेशी कंपनियों के संभावित निवेश पर भी बुरा प्रभावित होगा।

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के दो प्रमुख शेयरधारकों- वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिड़ला ग्रुप- ने सार्वजनिक शेयरधारकों के साथ कुल मिलाकर 1,90,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जिसमें से 1,65,000 करोड़ रुपये एफडीआई के जरिये निवेश किया गया। यदि बैंकों की उधारी और बकाये स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो कुल निवेश 3,00,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। जबकि पिछले दस वर्षों के दौरान कंपनी का संचयी घाटा वित्त वर्ष 2018-19 तक 55,175 करोड़ रुपये और और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण वित्त वर्ष 2020 की सितंबर तिमाही में 49,727 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया। ऐसे में अचानक परिचालन बंद होने अथवा कंपनी द्वारा दिवालिया आवेदन दायर करने से शेयरधारकों और निवेशकों के निवेश मूल्य का एक बड़ा हिस्सा बट्टेखाते में चला जाएगा। यह वोडाफोन पीएलसी द्वारा अपने बहीखाते में दर्ज किए गए बट्टेखाते से अतिरिक्त होगा।

वास्तव में इससे सरकार को भी जबरदस्त नुकसान होगा। वर्ष 2010 में एकीकृत कंपनी की स्थापना के बाद नीलामी के जरिये स्पेक्ट्रम खरीद के लिए उसे सरकार को 1,39,960 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। यदि वोडाफोन आइडिया का परिचालन बंद होता है तो सरकार को 89,180 करोड़ रुपये के भुगतान का नुकसान होगा। बकाये स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए उसे वित्त वर्ष 2034 तक ब्याज के साथ इस रकम का भुगतान करना है। कंपनी 54,467 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर चुकी है। इसके अलावा सरकार 44,150 करोड़ रुपये की भी वसूली नहीं कर पाएगी जिसके लिए वोडाफोन आइडिया का कहना है कि एजीआर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण उसे भुगतान करना पड़ेगा।

वोडाफोन आइडिया के बंद होने से सरकार को न तो लाइसेंस शुल्क का भुगतान हो पाएगा और न ही स्पेक्ट्रम उपयोगिता शुल्क का जो कंपनी के एजीआर का 13 फीसदी अथवा औसतन सालाना करीब 13,500 करोड़ रुपये है। इसके अलावा सरकार को जीएसटी, सीमा शुल्क एवं प्रत्यक्ष कर आदि विभिन्न करों के जरिये वोडाफोन आइडिया से प्राप्त सालाना करीब 13,600 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

वोडाफोन आइडिया के बंद होने से रोजगार पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा जो एक ऐसे बाजार में दिखेगा जहां रोजगार सृजन पहले से ही कम है। कंपनी के आकलन के अनुसार, उसका परिचालन बंद होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर 1,00,00 लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। विलय के दौरान उसने अपने कर्मचारियों संख्या पहले ही कम रखी थी।

इसके अलावा कई अन्य चुनौतियां भी दिख सकती हैं। वोडाफोन आइडिया का परिचालन बंद होने से उसके 30 करोड़ से अधिक ग्राहकों को भारती एयरटेल, रिलायंस जियो अथवा बीएसएनएल में पोर्टआउट होना पड़ेगा। कंपनी के 20 करोड़ 2जी ग्राहकों के लिए विकल्प काफी सीमित है क्योंकि जियो केवल 4जी सेवाएं मुहैया कराती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों कंपनियों के नेटवर्क पहले से ही अपने अधिकतम क्षमता पर काम कर रहे हैं और ऐसे में वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को तत्काल समायोजित करना आसान नहीं होगा।

वोडा आइडिया का होगा असर

- **भविष्य में विदेशी कंपनियों के एफडीआई निवेश पर विपरीत प्रभाव दिखेगा**
- **सरकार को 1,33,000 करोड़ रुपये और लाइसेंस शुल्क, एसयूसी एवं अन्य करों के कारण सालाना 27,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान**
- **प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर 1 लाख लोगों को खोना पड़ेगा रोजगार**
- **वोडाफोन आइडिया के करीब 20 करोड़ ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी ऑपरेटरों में पोर्ट करने की होगी परेशानी**

बाजार की प्रतिक्रिया से मिले दूरसंचार में दो फर्मों के संकेत

भारती एयरटेल का शेयर पांच फीसदी चढ़ा, लिहाजा उसका बाजार पूंजीकरण 2.57 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। वहीं वोडा आइडिया में 25 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई

कृष्ण कांत
मुंबई, 17 जनवरी

शेयर बाजार ने आज भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर समायोजित सकल राजस्व पर बकाया बकाया मामले में दूरसंचार कंपनियों की समीक्षा याचिका सर्वोच्च न्यायालय में ठुकराए जाने से पड़ने वाले वित्तीय असर पर अलग-अलग राय दी। एक ओर जहां भारती एयरटेल का शेयर निवेशकों की खरीदारी के दम पर नई ऊंचाई पर पहुंच गया, वहीं वोडाफोन आइडिया का शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया क्योंकि काफी निवेशकों ने इस शेयर की बिकवाली की।

भारती एयरटेल का शेयर पांच फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ, जिससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2.57 लाख करोड़ रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। इसकी तुलना में वोडाफोन आइडिया ने अपने बाजार पूंजीकरण का करीब एक चौथाई गंवा दिया। कारोबारी सत्र में निचले स्तर पर वोडाफोन गुरुवार के बंद भाव से करीब 50 फीसदी नीचे था।

विश्लेषकों ने कहा कि कीमतों की अलग-अलग चाल बताती है कि इक्विटी निवेशकों को वोडाफोन आइडिया का भविष्य लगातार अंधकारमय दिख रहा है, वहीं भारती एयरटेल को तेजी से एकीकृत हो रहे मोबाइल टेलीफोनी बाजार में विजेता के तौर पर देखा जा रहा है।

क्रेडिट सुइस ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के दो ऑपरेटर वाले परिदृश्य के करीब ला दिया है। क्रेडिट सुइस के वरुण आहूजा और विरल शाह ने एक रिपोर्ट में कहा है, पिछली नजीर को देखते हुए हमें मोबाइल ऑपरेटरों की याचिका की कामयाबी की काफी कम संभावना दिख रही थी। आदितत्य बिड़ला और वोडाफोन समूह, वोडाफोन आइडिया में इक्विटी लगाने के अनिच्छुक हैं, लिहाजा हम वोडाफोन आइडिया के दिवालिया की ओर बढ़ने की मजबूत संभावना है। भारती एयरटेल को इस क्षेत्र के एकीकरण से फायदा मिलेगा।

क्रेडिट सुइस के मुताबिक, निजी क्षेत्र के दो मोबाइल ऑपरेटरों के उभरने की संभावना 65 फीसदी है। बीएसएनएल की तरफ से वोडाफोन आइडिया के अधिग्रहण की संभावना या दिवालिया से कमजोर तीसरे ऑपरेटरों के उभरने की संभावना 29 फीसदी है और वोडाफोन के अस्तित्व में बने रहने की संभावना महज 15 फीसदी है।

न्यू स्ट्रीट रिसर्च के विश्लेषक भी वोडाफोन आइडिया को लेकर समान रूप से निराशावादी हैं। ब्रोकरेज ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है, वोडाफोन आइडिया के ऊपर 7 अरब डॉलर (करीब 50,000 करोड़ रुपये बकाया है जबकि भारती पर 5 अरब डॉलर (करीब 35,000 करोड़ रुपये) और इसका भुगतान 23 जनवरी तक किया जाना है। चूंकि वोडाफोन के पास रकम जुटाने का कोई जरिया नहीं है, लिहाजा पूरी संभावना है कि यह बाजार दो ऑपरेटरों वाले बाजार की ओर बढ़ेगा, जो भारती एयरटेल के लिए काफी सकारात्मक है।

भारती अब बाजार पूंजीकरण के लिहाज से वोडा-आइडिया से 20 गुनी बड़ी है

दोनों ब्रोकरेज फर्मों ने भारती एयरटेल के शेयर की लक्षित कीमत में इजाफा किया है और अस्तित्व को लेकर अनिश्चितता के कारण वोडाफोन की रेटिंग को निलंबित कर दिया है।

वित्तीय खाई दो फर्मों को अलग कर रही है और उनके बाजार पूंजीकरण में अब यह स्पष्ट नजर आ रहा है। शुक्रवार के बंद भाव पर भारती एयरटेल अब बाजार पूंजीकरण के लिहाज से वोडाफोन आइडिया के मुकाबले 20 गुना बड़ी है। अचल संपत्ति के मामले में भी भारती अब वोडाफोन के मुकाबले करीब 30 फीसदी बड़ी है। साल 2015 में एक समय वोडापोन आइडिया का बाजार पूंजीकरण भारती एयरटेल का आधा था।

आज के लाभ के साथ भारती एयरटेल अब बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की 12वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, जो एक साल पहले 21वें स्थान पर थी।

विश्लेषकों ने कहा, पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया के बाजार पूंजीकरण में तेज गिरावट ने कंपनी को अतिरिक्त संसाधन जुटाने में काफी मुश्किल खड़ी की है। सिटी रिसर्च के सौरभ हांडा ने कहा, मौजूदा बाजार पूंजीकरण के मुकाबले देनदारी दोगुने से ज्यादा होने से वोडाफोन आइडिया के लिए मौजूदा स्थिति काफी संकटपूर्ण व अनिश्चित हो गई है।

एडलवाइस सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने कहा, सरकारी हस्तक्षेप के अभाव में बाजार दो कंपनियों वाले बाजार में तब्दील हो जाएगा और यहां भारती एयरटेल व रिलायंस जियो का ही अस्तित्व रहेगा। भारती एयरटेल को हालांकि करीब 34,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे, लेकिन यह उसके लिए सकारात्मक होगा क्क्योंकि राजस्व में बढ़ोतरी लागत में बढ़ोतरी के बिना होगी। वोडाफोन आइडिया ने जुलाई-सितंबर 2019 की तिमाही में भारतीय कंपनी जगत का सबसे बड़ा नुकसान दर्ज करने के बाद अपनी बैलेंस शीट में तेज गिरावट देखी है।

वोडाफोन में निवेश पर म्युचुअल फंडों का अलग-अलग रुख

जश कृपलानी
मुंबई, 17 जनवरी

सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को दूरसंचार कंपनियों की समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद विभिन्न फंड हाउस अलग-अलग रुख अपना रहे हैं। कुछ योजनाएं वोडाफोन आइडिया में अपने निवेश का 100 फीसदी बट्टे खाते में डाल रही हैं, वहीं अन्य योजनाएं अभी इस पर फैसला नहीं ले पाई हैं कि संभावित डिफॉल्ट या रेटिंग के कदम से क्या परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की दरकार है या नहीं।

छह योजनाओं के जरिये वोडाफोन आइडिया में 2,073 करोड़ रुपये के निवेश (31 दिसंबर 2019) वाले फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ ने मौजूदा शेयरधारकों के हितों को सुरक्षित रखने के इरादे से इस कंपनी में अपने निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया है। इस वजह से इन योजनाओं के एनएवी में चार से सात फीसदी की गिरावट आई, जिसके जरिये दूरसंचार कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है। कुल मिलाकर फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ का कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश म्युचुअल फंड उद्योग के कुल निवेश का 61 फीसदी है। म्युचुअल फंड उद्योग का इस कंपनी में कुल निवेश 3,389 करोड़ रुपये है, जो 45 योजनाओं के जरिए किए गए हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसी स्थिति में फंड हाउस को सोच समझकर कदम उठाने की दरकार है ताकि एक निवेशक वर्ग को दूसरे वर्ग के मुकाबले फायदा न मिल जाए। एक फंड मैनेजर ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कुछ निवेशक इन योजनाओं से तत्काल रकम निकाल सकते हैं यानी डिफॉल्ट या रेटिंग में कमी की वास्तविक कवायद से काफी पहले। यह निवेशकों के निश्चित वर्ग को फायदा दे सकता है।

वोडाफोन आइडिया पर कुल बकाया 53,038 करोड़ रुपये है।

विशेषज्ञों ने कहा कि निवेश को बट्टे खाते में न डालने से उन निवेशकों को फायदा हो सकता है जो ऐसी योजनाओं से निवेश की निकासी करते हैं

दूरसंचार कंपनी ने कहा है कि वह संशोधित याचिका दाखिल करने समेत अन्य विकल्पों की तलाश कर रही है। फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ के कदम के बाद निप्पॉन इंडिया एमएफ ने भी वोडाफोन आइडिया में अपने निवेश को बट्टे खाते में डालने का फैसला लिया है।

विशेषज्ञों ने कहा, वोडाफोन आइडिया में जिन योजनाओं के जरिए सबसे ज्यादा आवंटन हुआ है, उनमें समय पर निवेश निकासी करने वाले निवेशकों के मुकाबले पर अलग तरह का असर दिख सकता है। वैल्यू रिसर्च के संस्थापक व मुख्य कार्याधिकारी धीरेंद्र कुमार ने कहा, यह सुनिश्चित करना फंड हाउस की जिम्मेदारी है कि ऐसी स्थिति में निवेशकों के एक वर्ग को दूसरों पर फायदा न मिलने पाए।

वोडाफोन में प्रॉविडेंट फंडों का निवेश

सचिन मामबटा
मुंबई, 17 जनवरी

सरकार की देनदारियों और उद्योग पर दबाव के बीच बड़े कर्ज से जूझ रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) में एक से ज्यादा प्रॉविडेंट फंडों ने निवेश किया था।

तीन प्रॉविडेंट एवं पेंशन फंड योजनाओं ने कंपनी के डिबेंचर में निवेश किया था। दूरसंचार कंपनी द्वारा नियामक के समक्ष मुहैया कराई गई जानकारी में कहा गया है कि इनमें राष्ट्रीय पेंशन योजना, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी फॉर बोकारो स्टील इम्पलॉयीज प्रॉविडेंट फंड और एमटीएनएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट शामिल हैं।

- **वोडाफोन के बंद होने की गहरा गई है आशंका**
- **निवेशकों में एनपीएस, बोकारो स्टील, एमटीएनएल शामिल**

विभिन्न अवसरों पर जारी बयानों के अनुसार, कंपनी के प्रवर्तक अतिरिक्त पूंजी लगाने को इच्छुक नहीं रहे हैं जिससे कंपनी के बंद होने की आशंका गहराने का संकेत मिलता है। निवेश की मौजूदा स्थिति भी सपष्ट नहीं थी। उदाहरण के लिए, नियामक को भेजी जानकारी में सितंबर 2019 के पत्र को भी शामिल किया गया है जिसमें कहा गया कि एमटीएनएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट को उसके निवेश के संबंध में पूरी रकम का भुगतान किया जा चुका है। यह लेनदेन बकाया राशि का पूर्व भुगतान था।

पत्र में कहा गया है, 'हम (एमटीएनएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट) इसकी पुष्टि करते हैं कि पूर्व-भुगतान की तारीख तक बकाया मूल राशि ब्याज सहित 4 सितंबर 2019 को चुका दी गई थी।'

पूर्व-भुगतान से संबंधित रकम पांच करोड़ रुपये थी। यह स्पष्ट नहीं है कि अन्य फंडों का कुल निवेश कितना हो सकता है।

अक्टूबर में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार वोडाफोन आइडिया को सरकार के 53,038 करोड़ रुपये चुकाने की जरूरत है।

कम पैसे में पॉलिसी बीमा क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं

सोमेश झा
नई दिल्ली, 17 जनवरी

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के चेयरमैन सुभाष सी खुंटिया ने बीमा उद्योग को चेताया है कि अगर पॉलिसी का प्रीमियम बहुत कम रखा जाता हैं तो उनका भी हश्र विमानन और दूरसंचार क्षेत्र जैसी हो जाएगा।

खुंटिया ने कहा कि समूह स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के मामले में एकत्र किए गए प्रीमियम का करीब 43 प्रतिशत इंश्योरेंस ब्रोकर लेते हैं। खुंटिया ने इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन आफ इंडिया की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, 'लेकिन मैं आपको सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दूंगा। हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, लेकिन हानि का अनुपात भी ज्यादा है। इस समय यह टिकाऊ नहीं है। बीमा कंपनियों मध्यस्थ और पॉलिसीधारकों को टिकाऊ वातावरण तैयार करना होगा।'

उन्होंने कहा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा के मामले में अन्य उद्योग खासकर उड्डयन और दूरसंचार, नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन उनके ग्राहकों को नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति बीमा उद्योग में नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसमें ग्राहकों की रक्षा करनी होती है। अगर बीमा उद्योग खराब स्थिति में पहुंचता है तो ग्राहक भी इससे प्रभावित होंगे और नियामक के रूप में हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो।

प्रतिस्पर्धा में कम प्रीमियम पर पॉलिसी दी तो होगी दुर्गति

- आईआरडीएआई के चेयरमैन ने कहा कि अगर उत्पाद की कीमतें बहुत कम रखी जाती हैं तो उनकी भी गति उड्डयन और दूरसंचार क्षेत्र जैसी हो जाएगी
- इस समय बीमा क्षेत्र टिकाऊ नहीं, बीमा कंपनियां, मध्यस्थ और पॉलिसीधारकों को टिकाऊ वातावरण तैयार करना होगा
- प्रीडेटरी प्राइसिंग पर लगाम लगाने के लिए न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि सुनिश्चित किया जाएगा कि उद्योग की सेहत न बिगड़े

नागरिक उड्डयन बहुत ही प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है, जहां कम किराये की स्थिति कुछ एयरलाइंस के लिए चिंता की वजह बन गई है। दरअसल सरकार ने बार बार इसके लिए प्रीडेटरी प्राइसिंग यानी प्रतिस्पर्धा और बाजार बिगाड़ने के के लिए दाम बहुत गिराने को जिम्मेदार बताया है। साथ ही उद्योग को चेताया भी है कि वह प्रतिस्पर्धा में दूसरे को बाहर करे के लिए उड़ान का किराया बहुत कम रख रही हैं।

इसी तरह से दूरसंचार उद्योग भी गलाकाट प्रतिस्पर्धा की वजह से दबाव में है। खासकर 3 साल पहले रिलायंस जियो के आने के बाद से ऐसी स्थिति बनी है। भारती एयरटेल और वोडाफोन को हाल में बड़ा नुकसान हुआ है।

यह पूछे जाने पर कि कंपनियों द्वारा अपना कारोबार बढ़ाने के लिए प्रीडेटरी प्राइसिंग का सहारा ले रही हैं, खुंटिया ने कहा, 'निश्चित रूप से'। उन्होंने कहा, 'नियामक को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उद्योग टिकाऊ तरीके से चले। इस पर (प्रीडेटरी प्राइसिंग पर) लगाम लगाने के लिए न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बीमा उद्योग की सेहत न खराब हो।'

नियामक ने बीमा ब्रोकरों से यह भी कहा कि अपना रिटर्न दाखिल करते समय वे ज्यादा सावधानी बरतें और कहा कि कि नियामक बीमा मध्यस्थों से जुड़े नियमन के समेकन पर काम कर रही है, जिससे तमाम नियमों से बचा जा सके।

उन्होंने कहा, 'मैंने अधिकारियों से कहा है कि मध्यस्थों से जुड़े नियमों की बहुलता हैऔर अलग अलग श्रेणियों के खास मानक के बजाय सबके लिए एक सामान्य मानक होने चाहिए। हमें सभी मध्यस्थों को एक नियमन के तहत लाए जाने की जरूरत है।'

आईआरडीएआई ने 6 साल पहले बीमाकर्ताओं, ब्रोकरो व अन्य के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को स्वचालित बनाने के लिए बिजनेस एनलटिक्स प्रोजेक्ट पेश किया था। खुंटिया ने कहा कि 459 ब्रोकरों में से करीब 80 प्रतिशत यानी 364 ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न दाखिल किया है। उन्होंने कहा, 'कुछ ब्रोकरों ने अपना सालना रिटर्न समय से दाखिल नहीं किया है और कुछ प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। हमें और ज्यादा अनुशासित होना होगा।'

बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाने जाने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि विदेशी अंशधारिता बढ़ाकर 74 प्रतिशत किए जाने को लेकर इस क्षेत्र के हिस्सेदारों से राय मांगी गई है और प्रतिक्रिया मिलने के बाद उसे सरकार के पास भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा, 'बीमा अधिनियम के मुताबिक अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा 49 प्रतिशत है। अगर यह बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जाती है तो स्वाभाविक रूप से अधिनियम में संशोधन करना होगा।' उन्होंने मालिकाना और नियंत्रण के बारे में कहा कि अब तक इस मसले पर कोई फैसला नहीं किया गया है।

(साथ में एजेंसियां)

गोयल के बयान से विदेशी निवेशकों में होगी निराशा

नेहा अलावधी और शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 17 जनवरी

निवेशकों व बहुराष्ट्रीय उद्योगों के संगठनों का कहना है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की एमेजॉन को लेकर दी गई हाल की प्रतिक्रिया लंबे समय से उसके रुख का हिस्सा है, जिससे पता चलता है कि सरकार घरेलू कारोबारियों के विचारों को अनुचित महत्त्व दे रही है और उन आवाजों को दबा रही है, जो उनके नीतिगत मामलों को प्रभावित करते हैं।

गुरुवार को गोयल ने कहा था कि एमेजॉन 1 अरब डॉलर अतिरिक्त निवेश की घोषणा करके भारत पर कोई एहसान नहीं कर रही है, वह भारत में हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त धन लगा रही है। इस बयान के एक दिन बाद गोयल ने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से अलग हटकर लिया गया है, लेकिन विदेशी निवेशकों ने कहा कि मंत्री की प्रतिक्रिया लंबे समय से चल रहे रुख का हिस्सा है।

द्विपक्षीय कारोबार से जुड़े वाशिंगटन के एक संगठन के पदाधिकारी ने कहा, 'विदेशी निवेशकों के लिए अपने पक्ष में तर्क करना कठिन हो गया है। सरकार ने ई-कॉमर्स, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों और न्यायाधिकरण की नीतियों के बारे में चर्चा की जगह कम कर दी है। संभव है कि सरकार कुछ मसलों पर चिंतित न हो, लेकिन हम अपनी चिंताएं रखने को लेकर स्वतंत्रता चाहते हैं।' उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से उनसे मिलने से मना कर दिया है।

विदेशी निवेशक चिंतित

- विदेशी निवेशकों से जुड़े लोगों का कहना है कि गोयल के बयान से भारत में निवेश को लेकर माहौल खराब होगा
- उनके मुताबिक भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को अपना पक्ष रखने की जगह कम कर दी है, यह स्थिति लंबे समय से
- संदेश गया है कि वाणिज्य मंत्री भारत में निवेश की परवाह नहीं करते

टेक्नोलॉजी उद्योग से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'मंत्री ने जो कहा, वह उन्हें नहीं कहना चाहिए था। अब निश्चित रूप से माहौल निवेश के विरुद्ध बनेगा। निश्चित रूप से भारत में काम करने वाला हर कोई राजनीतिक मजबूरियों से वाकिफ है, लेकिन इससे निवेशकों में अच्छा संदेश नहीं गया है।' बहरहाल उन्होंने यह भी कहा कि एमेजॉन जेफ बेजोस की यात्रा का और बेहतर प्रबंधन कर सकती थी।

एक बड़ी सोशल मीडिया फर्म के अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा कि गोयल की प्रतिक्रिया को निवेशकों के हिसाब से भविष्य के लिए बेहतर नहीं माना गया है और इससे संदेश गया है कि 'वाणिज्य मंत्री के रूप मे पर वह देश में निवेश को लेकर कोई परवाह नहीं करते।'

कई बहुराष्ट्रीय फर्मों के साथ काम करने वाली एक सलाहकार कंपनी से जुड़े एक और व्यक्ति ने कहा, 'इस समय बाजार की धारणा बेहतर नहीं है। बहरहाल निवेशक समुदाय मंत्री को जानता है और संभवत: इससे भारत में निवेशकों की दिलचस्पी कम नहीं होगी। बहरहाल ऐसे मामलों को और बेहतर कूटनीतिक तरीकों से हल किया जा सकता है।'

ऐसा लगता है कि गोयल के बयान का एमेजॉन पर भी असर पड़ा है। गुरुवार को एमेजॉन इंडिया की वेबसाइट पर कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस का एक पत्र डाला गया था, जिसमें कहा गया था कि कंपनी 2025 तक भारत में 10 लाख अतिरिक्त नौकरियों का सृजन कर सकती है। ग्राहकों, विक्रेताओं व साझेदारों को संबोधित करते हुए बेजोस ने पत्र में लिखा है, '60,000 से ज्यदा कारोबारी मेड इन इंडिया उत्पादों का निर्यात दुनिया भर में कर रहे हैं और उनका कुल निर्यात 1 अरब डॉलर पार कर रहा है।' बुधवार को एमेजॉन ने 2025 तक 10 अरब डॉलर के भारत में निर्मित सामान के निर्यात की प्रतिबद्धता जताई थी। कंपनी के नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि छोटे व मझोले कारोबारियों को ऑनलाइन लाने के लिए कंपनी 1 अरब डॉलर अतिरिक्त निवेश करेगी।

बेजोस के अखबार की भाजपा ने की आलोचना

रॉयटर्स
नई दिल्ली, 17 जनवरी

अमेरिकी अरबपति जेफ बेजोस की कंपनी एमेजॉन ने 2025 तक भारत में 10 लाख लोगों को नौकरियां देने की घोषणा की है, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दल ने बेजोस के अखबार की वाशिंगटन पोस्ट की संपादकीय नीतियों की आलोचना की है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विदेशी मामलों के विभाग के प्रमुख विजय चौथाईवाले ने किसी खास समाचार का उल्लेख किए बगैर कहा कि समाचार पत्र में भारत के बारे में कवरेज को लेकर 'ढेरों समस्याएं' हैं। यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले भारत के एक कैनिबेट मंत्री ने एमेजॉन की भारत में निवेश की योजना को कंपनी के पापों का प्रायश्चित करार दिया था।

बेजोस ने अपने दौरे के दौरान भारत की प्रशंसा करते हुए कहा था कि 21वीं सदी भारतीय सदी होगी और देश में गतिशीलता और ऊर्जा कुछ अलग तरह की है।

चौथाईवाले ने रॉयटर्स से कहा, 'कंपनी के रूप में मैं एमेजॉन का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कंपनी का नियमित ग्राहक हूं। जेफ बेजोस को घर जाने के बाद वाशिंगटन पोस्ट को बताना चाहिए कि उनकी क्या राय है।'

उन्होंने कहा, 'वॉशिंगटन पोस्ट की संपादकीय नीति बहुत ज्यादा पक्षपाती है और एक एजेंडे से संचालित होती है।' वॉशिंगटन पोस्ट की भारत की ब्यूरो प्रमुख जोआन्ना स्लैटर ने इस सिलसिले में रॉयटर्स की ओर से मांगी गई प्रतिक्रिया को समाचार पत्र के वॉशिंगटन प्रवक्ता को भेज दिया, जिन्होंने तत्काल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

चौथाईवाले इसके पहले राजनीतिक मसलों पर विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग की आलोचना करते रहे हैं, जिसमें कश्मीर विवाद भी शामिल है। उनका कहना है कि उनकी रिपोर्टिंग मोदी के खिलाफ पक्षपाती होती है। चौथाईवाले की टिप्पणी को लेकर एमेजॉन को भेजे गए ई-मेल का कोई जवाब नहीं मिला है।

वित्त मंत्रालय ने बढ़ाया जीएसटी का लक्ष्य

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 17 जनवरी

बजट के पहले वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के जनवरी और फरवरी महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूली का लक्ष्य बढ़ा दिया है। पहले जहां इन महीनों में 1.10 लाख करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य रखा गया था, वहीं अब हर महीने 1.15 लाख करोड़ रुपये वसूली की जाएगी। आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट की पहचान कर इस पर विशेष ध्यान देकर यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग की ओर से आयोजित बैठक के बाद मार्च के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह का लक्ष्य बरकरार रखा गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने पहले के लक्ष्य की तुलना में इन महीनों में 10,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त वसूली का लक्ष्य रखा है। यह फैसला ऐसे समय में हुआ है, जब अप्रैल महीने को छोड़कर चालू वित्त वर्ष के दिसंबर तक के प्रत्येक महीने में कर वसूली 1.10 लाख करोड़ रुपये से कम रही है।

पिछले महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए हर महीने 1.10 लाख करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें किसी एक महीने में 1.25 लाख करोड़ रुपये वसूली की जानी थी। बहरहाल दिसंबर का कर संग्रह 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2020 के 9 महीनों में से 4 महीनों में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से कम रहा है।

एनए शाह एसोसिएट्स के पार्टनर पराग मेहता ने कहा, 'अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए यह एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य है। यहां तक कि दीपावली के त्योहार के दौरान भी संग्रह महज 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को छू पाया।' इस बैठक में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया कि जीएसटी अधिकारियों को आपूर्ति व खरीद की रसीद की मिलान और मिलान न होने पर आंकड़ों का विश्लेषण करने, रिटर्न दाखिल न करने के मामले, ओवर इनवाइसिंग सहित जैसे मामलों को पर ध्यान देने की जरूरत है। अधिकारी यह भी देखेंगे कि अनुमति प्राप्त सीमा के अतिरिक्त रिफंड या फर्जी रिफंड नहीं दाखिल किया गया हो। सूत्रों ने कहा कि कर चोरी रोकने, फर्जी या भारी मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों की जांच, आंकड़ों के विश्लेषण की समीक्षा आदि पर भी जोर दिया गया है।

कृषि वस्तु विनिमय को तैयार ईरान

भाषा
मुंबई, 17 जनवरी

ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने आज कृषि क्षेत्र में भारत के साथ वस्तु के बदले वस्तु (बार्टर) व्यापार प्रणाली अपनाए जाने की वकालत की। साथ ही उन्होंने भारतीय बैंकों की ईरान में शाखाएं खोलने का भी सुझाव दिया ताकि ईरानी कंपनियां रुपये और रियाल में कारोबार कर सकें।

जरीफ ने यह भी कहा कि भारत को ईरान जैसा भरोसेमंद तेल आपूर्तिकर्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अमेरिकी डॉलर के दबदबे को खत्म करने के लिए अपनी-अपनी मुद्राओं में कारोबार करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक पाबंदी लगा रखी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने यह बात कही। ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव है। जरीफ ने कहा, 'एक बाधा अमेरिकी डॉलर में मूल्य ह्रास है। 70 के दशक से अमेरिका डॉलर का कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका को अपनी मुद्रास्फीति को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया के अन्य देश उसका भुगतान कर रहे हैं। इसका कारण अमेरिकी डॉलर का दबदबा होना है।'

उन्होंने कहा, 'अमेरिका अपनी मुद्रा को हथियार के रूप में उपयोग करता है। हमें इस पर आश्रित नहीं होना चाहिए।' जरीफ ने कहा कि भारत और ईरान को अपनी मुद्राओं में एक-दूसरे के साथ कारोबार करने की जरूरत है ताकि अगर ईरान भारत में कोई उत्पाद बेचता या खरीदता है तो उसे भुगतान के लिए डॉलर की जरूरत न पड़े।

मंत्री ने कहा, 'हम रुपये का उपयोग कर सकते हैं। हमारा भारत सरकार के साथ रुपया और ईरानी रियाल के उपयोग को लेकर समझौता है। लेकिन हमें इसे अपने लेन-देन में आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने की जरूरत है।'

बीएस सूडोकू 3642

								2
4	7	3	6				9	
			1				7	
					6	8		7
	8	1	2		7	9	5	
7		4	8					
	9				5			
	3				4	2	6	1
1								

परिणाम संख्या 3641

5	2	8	1	7	9	4	3	6
6	3	1	4	8	5	9	7	2
7	9	4	6	2	3	8	1	5
3	6	9	8	4	7	5	2	1
2	1	7	5	9	6	3	8	4
4	8	5	2	3	1	7	6	9
1	7	6	3	5	4	2	9	8
8	5	3	9	1	2	6	4	7
9	4	2	7	6	8	1	5	3

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 286

आम समझ से अलग

मोदी सरकार को अभी जो सबक सीखने हैं उनमें से एक यह भी है कि आर्थिक समस्याओं का हल आम समझ के प्रतिकूल भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जरूरी नहीं कि पहली नजर में जो आपको अच्छा लगे वही सही हो। जैसा कि हमने नोटबंदी के समय देखा, काले धन की समस्या का हल नकदी की जमाखोरी पर हल्लाबोल कर नहीं निकाला जा सका क्योंकि अधिकांश पुराने नोट रिजर्व बैंक के पास वापस आ गए।

इसी तरह कर में कमी का हल अनिवार्य तौर पर कर दरों में इजाफा करना नहीं है। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में थोड़े समय के लिए ही सही, यह हल सुझाया गया था। इसी तरह व्यापार घाटे का हल आयात प्रतिबंधित करना नहीं है। सन 1991 का अनुभव हमें दिखा चुका है कि व्यापक व्यापार घाटे का हल अर्थव्यवस्था को खोलना ही है, न कि संरक्षणवादी उपाय अपनाना। इसी प्रकार निर्यात को प्रोत्साहन देने का काम निर्यात सब्सिडी समाप्त करके अधिक बेहतर ढंग से किया जा सकता है, बजाय कि रुपये के बाहरी मूल्य को समायोजित करने के।

यदि हालिया अनुभवों को देखें तो लगता है कि ये अथवा ऐसे अन्य सबक सीखे नहीं गए हैं। ऐसे में औषधि कीमतों में बढ़ोतरी की प्रतिक्रिया स्वरूप कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। गत सितंबर में घरेलू बाजार में प्याज की कमी की प्रतिक्रिया स्वरूप निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसा कि डॉनल्ड ट्रंप की व्यापारिक नीतियों का विरोध करने वालों ने कहा भी था कि चीन से आने वाली वस्तुओं पर अतिरिक्त आयात शुल्क लागू करने से घरेलू आपूर्ति की लागत में इजाफा हुआ। जेपी मॉर्गन के अनुसार इससे एक परिवार के सालाना बजट में 1,000 डॉलर का बोझ पड़ा। भारत में भी किसी को ऐसी कवायद करनी चाहिए ताकि इस्पात आयात पर लगे अतिरिक्त शुल्क, टैरिफ बढ़ोतरी और देश को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी, कुछ वस्तुओं के आयात पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क आदि की लागत निकाली जा सके। इसके अलावा मलेशिया से पाम ऑयल के आयात पर लगे प्रतिबंध और तुर्की से पेट्रोलियम आयात पर रोक आदि की भी लागत निकाली जानी चाहिए।

इसके बाद जेफ बेजोस और एमेजॉन को लेकर हमारी प्रतिक्रिया में बेअदबी की झलक रही। विश्व व्यापार में एक फर्म के भीतर होने वाले कारोबार और वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बनने के महत्त्व को देखते हुए बेजोस के 10 अरब डॉलर के अतिरिक्त निर्यात के वादे की सरकार को सराहना करनी चाहिए थी या कम से कम शांत रहना चाहिए था। परंतु इसके उलट सरकार का उत्तर मित्रतापूर्ण होने से कोसों दूर था। यकीनन इसमें इस तथ्य का भी योगदान होगा कि बेजोस एक समाचार पत्र के मालिक भी हैं जो मोदी सरकार का आलोचक है।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

इसके अतिरिक्त छोटे व्यापारियों की लॉबी का दबाव भी होगा जिन्हें डर है कि वे भारी नकदी वाली एमेजॉन जैसी कंपनी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही समस्याओं से निपटने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था। हालांकि वह उस वक्त कदम नहीं उठाता जब उसे उठाना चाहिए। जियो का मामला हमारे सामने है। व्यापक बात यह है कि छोटे स्टोर मालिकों के पास यह क्षमता नहीं है कि वे व्यापक आपूर्ति शृंखला बना सकें। वे विनिर्माण आधार भी नहीं बना सकते और न ही गुणवत्तापूर्ण रोजगार दे सकते हैं। जाहिर है सरकार का रुख गलत था।

झारखंड इसका विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है जहां वस्त्र उद्योग में नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी प्रति माह 5,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह देश में वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा की कमी को दर्शाता है। ध्यान रहे कि श्रम की लागत को प्रतिस्पर्धा में कमी की सबसे अहम वजह नहीं माना जा सकता है क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक है जबकि उसकी श्रम लागत काफी ज्यादा है। हालांकि उक्त सब्सिडी पर उद्योग जगत सकारात्मक दिख रहा है। परंतु इसे अच्छी खबर मानने में संदेह ही है।

किसी भी उद्योग को यदि व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा तो वह निवेश करेगा लेकिन करदाताओं के पैसे का इससे कहीं बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेहतरीन की तलाश में ऐसे तमाम शिथिल समझौते कर लिए जाते हैं जो दिक्कतदेह हो सकते हैं। ऐसे समझौतों से ही उच्च लागत वाली ऐसी अर्थव्यवस्था निर्मित हो जाती है जिसके साथ हम लंबे अरसे तक रहे और अभी हाल फिलहाल तक हम जिससे दूरी बनाने में लगे थे।

बिनय सिन्हा

अमेरिका में असमानता को सामने रखते शैक्षणिक तथ्य

शैक्षणिक आंकड़ों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि अमेरिका के समाज में असमानता बढ़ी है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **पार्थसारथि शोम**

गत माह अपने स्तंभ में मैंने अमेरिका में बढ़ती असमानता का जिक्र किया था। बीसवीं सदी के अंत तक वहां आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ चुकी थी तथा आय और संपत्ति की असमानता में इजाफा हुआ था। जो भी लाभ थे वे आबादी के एक छोटे हिस्से को मिले जो शीर्ष पर था। सन 2003 में जब थॉमस पिकेटी और एमेनुएल साएज ने पर्चे में फ्रांसीसी आंकड़ों का इस्तेमाल करके यह दर्शाया था कि सन 1970 और 1980 के दशक में शीर्ष पर आय और उसके घटकों में चक्करदार वृद्धि देखने को मिली थी। उसके बाद कर आंकड़ों के इस्तेमाल से विश्लेषण का चलन बढ़ा था।

बाजार का तथाकथित 'प्राकृतिक कानून' जो आश्वस्त करता था कि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का लाभ सभी को मिलेगा, वह विफल हो गया। पूंजी पर प्रतिफल की दर आर्थिक वृद्धि की दर से आगे निकल गई और असमानता में इजाफा होने लगा। आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र के जानकार रॉबर्ट सोलो ने दोहराया कि समतामूलक वृद्धि केंद्रीय आर्थिक विषय है। आय का वितरण तेजी से असमान होता गया। संपत्ति के आगमन ने इसमें अहम भूमिका निभाई। संपत्ति का एक हिस्सा जिसमें पैसा, परिसंपत्ति, शेयर, बॉन्ड और अन्य तरह की पूंजी शामिल है, को छिपाया जा सकता है। गैब्रिएल जकमैन के अनुसर विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 11.5 फीसदी हिस्सा यानी करीब 8.7 लाख करोड़ डॉलर की राशि विदेशी खातों में छिपाई गई है।

आय और संपत्ति वितरण की स्थिति खराब होने से वृहद आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण होने लगा और यह सामने आने लगा कि कैसे खराब वितरण ने अर्थव्यवस्था और उसकी गतिविधियों को प्रभावित किया। हीथर बाउशे ने इसकी व्यापक समीक्षा की। राज चेट्टी ने असमानता को कुछ इस प्रकार देखा, 'आय वितरण को देखा जाए तो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के कुछ ही बच्चे अपने माता-पिता से बेहतर स्थिति में हैं।' ऐसा करते हुए वह सन 1960 और 1970 के दशक की उपलब्धियों का प्रतिकार करते हैं। चेट्टी तथा अन्य का अनुमान है कि यदि आय और संपत्ति में असमानता पर नियंत्रण रहता तो विशुद्ध गतिशीलता में 70 फीसदी की कमी नहीं आती।

आर्थिक असमानता से स्वास्थ्यगत असमानता उत्पन्न हुई और लोगों द्वारा हासिल किए जाने वाले कौशल में भी अंतर आया। क्लॉडिया गोल्डिन, लॉरेंटस काट्ज, जैनेट क्यूरी, डगलस अलमॉन्ड और डंकन थॉमस ने इसे कई तरह से दर्शाया।

ब्रिटेन में एक ही सप्ताह में पैदा हुए 17,000 बच्चों पर किशोरावस्था में अध्ययन किया गया कि पता चला कि जो बच्चे स्वस्थ थे उन्होंने हाईस्कूल अंग्रेजी और गणित अच्छे से पास की। उन्हें रोजगार भी ज्यादा मिले और 33 वर्ष की उम्र में उनका वेतन भी दूसरों से अधिक था। इसी आधार पर सन 1999 में क्यूरी और रोजमैरी हायसन ने यह नतीजा निकाला कि जन्म के समय बच्चों के स्वास्थ्य का संबंध बड़ी उम्र में उनके स्वास्थ्य से है। वहीं वयस्क रोजगार का संबंध जन्म के समय कम वजन से है। स्पष्ट है कि विद्यालय में बच्चों और परिवार का व्यवहार तथा बिताए गए वर्ष काफी हद तक भविष्य का निर्धारण करते हैं। महामारीविद डेविड बार्कर ने बीमारियों के मामले में जेनेटिक या खराब जीवन शैली के बजाय माओं के पोषण और स्वास्थ्य को अहम बताया। अन्य लोगों ने जन्म के समय के वजन को हाईस्कूल पास करने की संभावना से जोड़ा। शोधकर्ताओं ने माना कि मातापिता की स्थिति जीवन भर प्रभावित करती है।

शिक्षा में अंतर का संबंध भी असमानता से है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के 31 देशों में बच्चों का ध्यान रखे जाने की बात करें तो इस क्रम में अमेरिका 20वें स्थान पर आता है। वहीं प्रीस्कूल नामांकन के मामले में वह 29वें स्थान पर है।

संयुक्त लेखन करने वालों द्वारा करीब आधी सदी पहले कम आय वर्ग वाले मिशिगन परिवारों के 123 अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि 3-4 वर्ष की उम्र में बच्चे यादृच्छिक रूप से बेहतर गुणवत्ता वाले प्रीस्कूल में शामिल हुए या उससे बाहर रहे। जब ये बच्चे 40 के आसपास की उम्र में पहुंचे तो जिन बच्चों ने प्रीस्कूल की पढ़ाई की थी उनके स्कूली पढ़ाई पूरी करने का प्रतिशत ज्यादा था। कॉलेज में भी वे ज्यादा गए, उनकी आय अधिक थी, आवास के मामले में स्थायित्व था और पारिवारिक रिश्तों में बेहतरी थी।

शिक्षा में अंतर, संसाधनों तक पहुंच में अंतर के रूप में भी सामने आता है। केरिस कूपर और किटी स्टीवर्ट ने सन 1988 से 2012 के बीच के शोध के आधार पर निष्कर्ष दिया कि गरीब बच्चों का प्रदर्शन उनकी गरीबी की बदौलत खराब रहा। स्पष्ट था कि उन परिवारों के पास पैसा पहुंचने पर उनका प्रदर्शन बेहतर होता।

केवल नकदी नहीं बल्कि मां का पोषण, साफ पेयजल, प्री-स्कूल सेवाएं, स्कूल की गुणवत्ता, पड़ोस की सुरक्षा, पुस्तकालय, पार्क, चिड़ियाघर, संग्रहालय आदि सभी का बच्चों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। बेहतर परिवार कल्याण के लिए माता-पिता को सवैतनिक अवकाश देने की बात की गई। हालांकि अमेरिका इस मामले में भी यूरोप से पीछे है। गैरे रामे और वैलेरी रामे की दलील है कि कॉलेज शिक्षा प्राप्त मां-बाप बच्चों के साथ अधिक समय बिताते हैं ताकि उन्हें शीर्ष कॉलेजों में दाखिला मिल सके। जाहिर है ऐसा न होने पर बच्चे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे।

नतीजा पेश करते हुए बाउशे का कहना है कि बच्चों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव को समग्रता में देखना होगा।

बाउशे के मुताबिक इसके लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए: (1) हर बार जब आधिकारिक रूप से आय और संपत्ति में वृद्धि के आंकड़े दिए जाएं तो बताया जाए कि आय और संपत्ति का वितरण किस प्रकार हुआ। (2) अवसरों को शीर्ष लोगों तक सीमित न रहने दिया जाए क्योंकि इससे अन्य लोगों के अवसर या लाभान्वित होने की संभावना प्रभावित होती है। (3) इसे हासिल करने के लिए सामाजिक आर्थिक नीति ऐसी हो कि बेहतर बाल स्वास्थ्य, प्रीस्कूल, सरकारी स्कूल और जन स्वास्थ्य हासिल किया जा सके। (4) बुनियादी निवेश को प्राथमिकता दी जाए। (5) समुचित प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने और आर्थिक वृद्धि को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने वालों का नियमन। (6) एकाधिकार पर लगाम ताकि अधिक सरकारी राजस्व अर्जित किया जा सके, उसका इस्तेमाल जरूरी व्यय में किया जा सकता है। (7) कामगारों की सामूहिक मोलभाव की क्षमता में इजाफा और (8) ऐसे वित्तीय उत्पादों में पूंजी निवेश को हतोत्साहित करना जो वास्तविक उत्पादक गतिविधि में शामिल नहीं होते या आर्थिक स्थिरता नहीं बढ़ाते।

चैनल शुल्क में बदलाव पर ट्राई बनाम भारतीय प्रसारक

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) एक असंभव काम करने में सफल रहा है। इसने भारतीय प्रसारकों को एकजुट कर दिया है। देश की हरेक बड़ी प्रसारक कंपनी के प्रमुख पिछले हफ्ते मुंबई में एक मंच पर इकट्ठा हुए थे। इनमें सोनी के एन पी सिंह, ज़ी के पुनीत गोयनका, डिज्नी-स्टार के उदय शंकर और टीवी टुडे के अरुण पुरी भी शामिल थे। ये सभी 74,000 करोड़ रुपये आकार के भारतीय टीवी बाजार में हिस्सेदारी के लिए कड़ी प्रतिस्पर्द्धा करते रहे हैं। उन्होंने कभी भी एक दूसरे के लिए कुछ नहीं बोला है। लेकिन भारतीय प्रसारण फाउंडेशन (आईबीएफ) के एक संवाददाता सम्मेलन में ये सभी एक सुर में बोलते हुए सुनाई दिए। यह काफी असामान्य है लेकिन यह समय ही असामान्य है।

इस साल 1 जनवरी को ट्राई ने 11 महीने पहले लागू की गई शुल्क व्यवस्था में कुछ बदलावों की घोषणा की है। इन बदलावों के संदर्भ में ही आईबीएफ ने 10 जनवरी को यह संवाददाता सम्मेलन किया था। उसके बाद ट्राई ने 13 जनवरी को अपना संवाददाता सम्मेलन कर अपनी बात रखी। उसके अगले दिन आईबीएफ और उसके प्रसारक सदस्यों ने शुल्क व्यवस्था में बदलावों को चुनौती देते हुए बंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है।

दुनिया के दूसरे बड़े टेलीविजन बाजार और उसकी नियामक संस्था के बीच चाहतों का टकराव बदस्तूर जारी है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक टीवी उद्योग या तो पतनशील हो जाए या फिर ट्राई को यह अहसास हो जाए कि बेहद प्रतिस्पर्द्धी बाजार में प्रसारकों को अपनी इच्छा के मुताबिकचैनल का शुल्क तय करने का पूरा अधिकार है। और यह पहलू भी महत्त्वपूर्ण है कि मनोरंजन, खेल, फिल्म या संगीत की कीमत वॉयस या डेटा या खाद्यान्न की तरह तय नहीं की जा सकती है। बंडल में चैनल मिलने से असल में उपभोक्ताओं को फायदा होता है। लेकिन बार-बार नियमों में बदलाव करने से एक नकारात्मक चक्र बनता है जो वृद्धि, नौकरी, कर और उपभोक्ता पसंद जैसे तमाम नियामकीय पहलुओं को प्रभावित करता है।

यह लड़ाई खत्म हो सकती है अगर प्रसारक और वितरक एकजुट होकर अपनी बात रखना सीख लें। देश में निजी टेलीविजन के उदय के 28 साल बाद भारत में केबल टीवी की औसत कीमत दुनिया भर में सबसे कम वाली श्रेणी में है और यह मुद्रास्फीति दर से भी नीचे बनी रही है। फिर भी कोई एक ग्राफ या चार्ट ऐसा नहीं है जो इस बड़े उद्योग के कीमत पहलू को रेखांकित कर सके और उपभोक्ताओं एवं नियामकों को अवगत करा सके।

दोनों पक्षों का यह टकराव निश्चित तौर पर तभी खत्म होगा जब ट्राई साधारण प्रभाव विश्लेषण करना सीख लेता है। नियमन करने या नहीं करने से जुड़े प्रभावों एवं लागत का विश्लेषण करने के लिए जबरदस्त दृढ़ता की जरूरत है। यह टीवी उद्योग की रक्षा करेगा और उपभोक्ताओं को भी पीड़ा से बचाएगा। ब्रिटेन के ऑफकॉम जैसे संचार नियामक नियमित रूप से यही काम करते हैं। अगर ट्राई ने नए नियम लागू करने से पहले संभावित असर का विश्लेषण किया होता तो वह महज एक साल पहले जारी आदेश में ढेरों बदलाव लागू नहीं करता।

सबसे पहले वर्ष 2016 में टीवी चैनलों को लेकर शुल्क व्यवस्था रखी गई थी। उसमें चैनलों की अधिकतम कीमत तय की गई थी और बंडलिंग को लेकर तमाम कायदे-कानून बनाए गए थे। लंबी अदालती कार्यवाही के बाद इसे फरवरी 2019 में जाकर लागू किया जा सका था। इससे पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली लेकिन इसने कीमतें बढ़ाने का भी काम किया। चैनलों के जटिल पैकेज से परेशान होकर उपभोक्ता केबल से डीटीएच या टीवी से ऑनलाइन का रुख करने लगे। शिकायतें बढ़ने के बाद ट्राई ने अगस्त 2019 में एक परामर्श-पत्र पेश किया था जो बंडलिंग के खिलाफ शेखी बघारने जैसा था। उसके बाद यह आदेश आया है।

अगर ट्राई का नया आदेश लागू किया जाता है तो कीमतों में और तेजी आएगी, चैनल एवं पैकेज पर संशय बढ़ेगा और इन बदलावों के बारे में सूचित करने पर भी अधिक पैसे खर्च करने होंगे। इसका मतलब लाइफस्टाइल चैनल, कई खेल चैनल और विशिष्ट चैनलों का खात्मा भी होगा। इससे नौकरियों एवं कर राजस्व का भी नुकसान होगा। यह काफी कुछ एक ऐसे साल में घटित हो रहा है जब आर्थिक सुस्ती ने विज्ञापन वृद्धि को दो अंकों से घटाकर एक अंक में ला दिया है।

ट्राई अक्सर कीमतों के मुद्दे पर जोर देता है। पिछला आदेश लागू होने पर 100 फ्री-टु-एयर चैनलों के लिए हर घर से प्रति माह 130 रुपये का नेटवर्क क्षमता शुल्क वसूलने की व्यवस्था लागू की गई जिससे कीमतें बढ़ गईं। नए आदेश में इसे बढ़ाकर 200 चैनलों के लिए अधिकतम 160 रुपये कर दिया गया है। ऐसे में हर टीवी कनेक्शन पर मासिक शुल्क बढ़ना लाजिमी है।

इस बिंदु पर बंडलिंग को लेकर ट्राई की कवायद का कोई मतलब नहीं दिखता है। वैश्विक स्तर पर बंडलिंग अधिकांश उद्योगों में की जा चुकी है। एयरलाइंस, होटल, मीडिया, उपभोक्ता उत्पाद और सबसे खास क्षेत्र दूरसंचार में भी यह संपन्न हो चुका है। होटलों में बंडलिंग के चलते बफे अपेक्षाकृत सस्ते हैं और उनमें लॉ कार्ते भोजन की तुलना में अधिक विविधता भी होती है। जी कैफे जैसा खास मिजाज का चैनल अधिक महंगा होगा अगर वह एक बंडल का हिस्सा नहीं है जिसमें अधिक मशहूर ज़ी टीवी है।

ट्राई के पास बड़ी मात्रा में शोध संसाधन, ढेर सारे आंकड़े और हितधारकों तक पहुंच है। एक नियामक के रूप में वह प्रभाव विश्लेषण के तरीके समझने के लिए दूसरे देशों के नियामकों से संपर्क साध सकता है। उससे टीवी उद्योग, उपभोक्ता और खुद ट्राई भी शुल्क नियमों में हो रहे बदलावों के असर से बच सकेंगे।

कानाफूसी

जन्मदिन पर धक्कामुक्की

बीते तमाम वर्षों के दौरान बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए एक खास दिन रहा है। पार्टी कार्यकर्ता उनके जन्मदिन पर न केवल भारी जलसा मनाते हैं बल्कि बहुजन आंदोलन को भी नई गति प्रदान की जाती है। प्रशंसकों में बहनजी के नाम से प्रसिद्ध मायावती अपने जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में मनाती हैं। बुधवार को उनके 64वें जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं में केक खाने के लिए होड़ मच गई। इस दौरान पार्टी कार्यालयों में धक्कामुक्की जैसी स्थिति बन गई। आलोचकों ने कहा कि ऐसे अवसरों पर इस तरह के दृश्य आम हो गए हैं और इससे खुद को बहुत अनुशासित पार्टी कहने वाली बसपा का नाम खराब हो रहा है।

कांग्रेस में ऊहापोह

कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की दिल्ली इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की। उन्होंने इन नेताओं से कहा कि वे 8 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी की ओर से लड़ें। लेकिन कई प्रमुख नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन अमेरिका चले गए हैं। उनकी बेटी बीमार है। माकन ने दिल्ली मामलों के प्रभारी पीसी चाको को बता दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता नसीब सिंह भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दिलचस्प है कि पार्टी ने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित से चुनाव लड़ने को कहा ही नहीं।

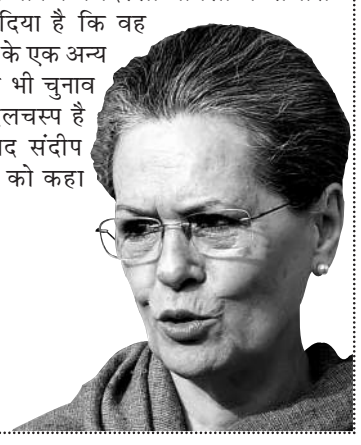

आपका पक्ष

राज्य नागरिकों को दें आधारभूत सुविधाएं

देश के सभी राज्यों को पुरुषों और महिलाओं को जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन मुहैया कराना चाहिए। उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करनी चाहिए। वे कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी व्यवस्था, बेरोजगार के मामले में शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी एवं असमर्थता या अयोग्यता के मामले में सहायता करें। राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कार्य की मानवीय स्थितियों, जीवन का शालीन स्तर और उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की पूर्ण सहभागिता प्राप्त करने के प्रयास करें। आर्थिक क्षेत्र में राज्य को अपनी नीति इस तरह से बनानी चाहिए ताकि सार्वजनिक हित के सहायक होने वाले भौतिक संसाधनों का वितरण का स्वामित्व एवं नियंत्रण हो और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक प्रणाली कार्य के फलस्वरूप धन का और उत्पादन के साधनों का जमाव सार्वजनिक हानि के लिए नहीं हो। राज्यों के बच्चों के लिए अवसरों और सुविधाओं की व्यवस्था की जाए जिससे उनका विकास अच्छी तरह से हो। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य की जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा की जाए। पूरे देश में एकसमान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्द्धन तथा मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने की जरूरत है। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा करने, वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने की भी जरूरत है।

हरिओम हंसराज, सारण

देश के भविष्य के लिए 10वीं तक की शिक्षा को निःशुल्क करना चाहिए

बेरोजगारी दूर करने के उपाय

देश की आर्थिक स्थिति मंद पड़ी हुई है। बेरोजगारी की समस्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। इससे उबरने के लिए सरकार को कुछ ठोस उपाय करने चाहिए। सबसे पहले सरकार को चीन को भारत के बाजार में आने से रोकना चाहिए। इसके साथ-साथ देश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे रोजगार सृजन हो सके। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भारतीय बाजार को विदेशों में फैलाने की जरूरत है। सरकार को सरकारी पूंजी को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। सरकार को महंगाई पर भी काबू पाना होगा। इसके अलावा जो नेता राजनीति के लायक नहीं हैं उनकी राजनीति से छुट्टी कर देनी चाहिए। इन सभी उपायों से देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा जिससे देश में बेरोजगारी की दर कम हो सकेगी।

भूपेंद्र सिंह रंगा, पानीपत

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

चीनी उत्पादन 26 प्रतिशत गिरा

देश की चीनी मिलों ने 1 अक्टूबर से 15 जनवरी के बीच पिछले साल के मुकाबले 26 प्रतिशत कम उत्पादन किया है। सूखे की मार झेल चुके महाराष्ट्र में कम उत्पादन के कारण उत्पादन में गिरावट आई है। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस्मा ने एक रिपोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र में मिलों ने 25.5 लाख टन चीनी उत्पादन किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि के 57 लाख टन उत्पादन की तुलना में कम है। वर्ष 2019-20 में देश का चीनी उत्पादन 20 प्रतिशत गिरकर 2.63 करोड़ टन रह सकता है। यह तीन साल का निचला स्तर है। वर्ष 2018 में सूखे की वजह से किसानों को गन्ना बुआई में कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था और वर्ष 2019 में प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में बाढ़ से फसल को नुकसान पहुंचा था। *रॉयटर्स*

हर ग्राम पंचायत में एफपीओ : योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि हमारा लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों में कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) खोलने का है और पहले चरण में राज्य के सभी ब्लॉकों, दूसरे चरण में न्याय पंचायतों और तीसरे चरण में सभी ग्राम पंचायतों में एफपीओ खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 336 एफपीओ खोले जा चुके हैं। *भाषा*

चने की रिकॉर्ड बुआई से तेजी खत्म

मध्य प्रदेश में इस बार बुआई सुस्त लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र में रकबा बढ़ा

सुशील मिश्र
मुंबई, 17 जनवरी

चालू सीजन में राजस्थान और महाराष्ट्र में चने की रिकॉर्ड बुआई से इसका रकबा नया रिकॉर्ड बनाने के करीब पहुंच गया है। चालू सीजन में चने की बुआई 105 लाख हेक्टेयर पार कर चुकी है। इसका रकबा बढ़ने और बेहतर फसल होने की संभावना से इस साल देश में चने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। पैदावार बढ़ने के अनुमान से चने में गिरावट शुरू हो गई है। मौजूदा फसल अनुमान को देखते हुए अगले महीने तक चने के भाव में तेज गिरावट की आशंका जताई जा रही है।

कृषि मंत्रालय के अनुसार 16 जनवरी तक देशभर में 105.351 लाख हेक्टेयर में चने की बुआई हो चुकी है जो पिछले साल 95.442 लाख हेक्टेयर में हुई थी। देश में चने का सामान्य रकबा 93.53 लाख हेक्टेयर माना जाता है और इस समय तक सामान्यत: 94.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई होने का अनुमान था। देश में सबसे ज्यादा चने की बुआई फसल सीजन 2017-18 में 105.951 लाख हेक्टेयर में हुई थी। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक चालू सीजन में चने का रकबा अब तक के बुआई के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है।

हालांकि चना उत्पादक प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश में इस बार चने की बुआई पिछले साल के 34.32 लाख हेक्टेयर से गिरकर 27.38 लाख हेक्टेयर तक ही हो सकी है। लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बुआई हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अभी तक राजस्थान में 21.38 लाख हेक्टेयर में चने की बुआई हुई है जबकि पिछले साल यह 15.03 लाख हेक्टेयर था। राजस्थान में चने का सामान्य रकबा 14.49 लाख हेक्टेयर माना जाता है। महाराष्ट्र में अभी तक 20.38 लाख हेक्टेयर में चने की बुआई हो चुकी है जबकि पिछले साल 12.70 लाख हेक्टेयर था। कर्नाटक में 12.27 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 5.87 लाख हेक्टेयर में चने की बुआई हुई है जो पिछले साल के लगभग बराबर ही है।

चने का रकबा और अच्छी फसल होने से इस बार उत्पादन नया रिकॉर्ड बना सकता है। सरकारी अनुमान के मुताबिक इस बार देश में चना का उत्पादन बढ़कर 116 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले साल 2018-19 के दौरान चना का उत्पादन अनुमानत: 101.3 लाख टन था। उत्पादन अधिक होने के अनुमान के साथ चने की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है।

हाजिर बाजार में करीब एक महीने पहले चने का भाव 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया था जो इस समय गिरकर 4,300 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। वायदा बाजार में भी चने का भाव गिरकर 4,250 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पहुंच गया है। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स में चने का भाव गिरकर (मार्च अनुबंध) 4,262 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया जबकि करीब एक महीने पहले (23 दिसंबर को) इसका भाव 4,535 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था।

कारोबारियों की मानी जाए तो अगले एक महीने चने में करीब 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट हो सकती है। मंडियों में में चने का भाव टूटना शुरू हो गया है जो आने वाले दिनों में आवक बढ़ने के साथ और तेजी से टूट सकते हैं। जयपुर मंडी में चना 4,400 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे लुढ़क गया है जो एक महीने पहले 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका था। फरवरी के अंत तक चने की नई फसल मंडियों में आएगी। फरवरी तक राजस्थान की मंडियों में चना 3,500-3,600 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है।

देश में चने का रकबा

साल	चने का रकबा	चने का उत्पादन
2014-15	84.14	73.3
2015-16	89.07	93.8
2016-17	98.48	93.8
2017-18	105.95	113.8
2018-19	95.44	101.3
2019-20	105.35	116.0*

16 जनवरी तक का रकबा लाख हेक्टेयर, *वर्ष 2019-20 का उत्पादन लक्ष्य लाख टन में, *स्त्रोत - कृषि मंत्रालय*

लौह अयस्क पर शुल्क छूट चाहते हैं खनिक

जयजित दास
भुवनेश्वर, 17 जनवरी

बजट से पहले व्यावसायिक खनिकों ने 58 से 63 प्रतिशत के एफई (लौह) ग्रेड वाले लौह अयस्क पर 30 प्रतिशत निर्यात शुल्क को माफ किए जाने की मांग की है। भारतीय खनिज उद्योग संघ (फिमी) के जरिये खनिकों ने निर्यात शुल्क से छूट दिए जाने पर जोर दिया है, क्योंकि देश में बेस ग्रेड के अयस्क के खरीदार कम हैं। निर्माता इस्पात निर्माण की लागत नियंत्रित रखने के प्रयास में अच्छे ग्रेड के अयस्क का इस्तेमाल करते हैं।

घरेलू बाजार में कम ग्रेड के अयस्क की सुस्त मांग के बीच निर्यात ही उपयुक्त दिख रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय को सौंपे अपने बजट-पूर्व ज्ञापन में फिमी ने कहा है कि खदानों में लौह अयस्क की मात्रा बढ़कर 16.285 करोड़ टन (31 मार्च 2019 तक) पर पहुंच गया था। इसका ज्यादातर हिस्सा ओडिशा और झारखंड में था। ज्यादातर लौह अयस्क में 58 से 62 प्रतिशत तक के एफई ग्रेड का अयस्क शामिल है जिसके निर्यात पर 30 प्रतिशत शुल्क लगता है, जबकि 58 प्रतिशत एफई ग्रेड के लौह अयस्क के लिए यह शुल्क लागू नहीं है।

फिमी के दावे के अनुसार, कम ग्रेड के अयस्क (58 प्रतिशत तक के फी ग्रेड) की मांग की चमक अंतरराष्ट्रीय बाजार में फीकी पड़ रही है। इसके अलावा, इसके निर्यात से जुड़े गोवा में खदानें मार्च 2018 से बंद हैं।

निर्यात शुल्क में मिले छूट

- खनिकों ने 58 से 63 प्रतिशत के एफई (लौह) ग्रेड वाले लौह अयस्क पर 30 प्रतिशत निर्यात शुल्क माफ किए जाने की मांग की
- कम ग्रेड के अयस्क की घरेलू बाजार में सुस्त मांग के बीच निर्यात ही उपयुक्त विकल्प रह गया है

फिमी ने अपने बजट-पूर्व अनुरोध में कहा है, '62 प्रतिशत एफई ग्रेड के लिए शुल्क निर्यात में छूट से खदानों में लौह अयस्क के बड़े भंडार की बिक्री करने में मदद मिलेगी जिससे विदेशी मुद्रा आय में इजाफा होगा। इसलिए संघ ने 62 प्रतिशत तक एफई ग्रेड के लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क पूरी तरह हटाए जाने का अनुरोध किया है।'

खदानों में लौह अयस्क के बढ़ते भंडार को जल्द निकाले जाने की जरूरत होगी क्योंकि व्यावसायिक खदानों में पट्टे की वैधता 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो रही है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 17	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,794.0	3.9	2,067.8	8.2
Copper	6,300.5	10.0	6,583.2	9.7
Nickel	14,290.0	-12.5	14,770.0	-14.5
Lead	2,027.0	-7.4	2,208.5	4.1
Tin	17,705.0	3.7	18,497.7	4.1
Zinc	2,438.0	-0.8	2,630.5	0.1
Gold ($/ounce)	1,558.4*	4.5	1,741.7	4.2
Silver ($/ounce)	18.1*	3.0	20.4	3.0
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	65.0*	9.2	64.7	8.7
Natural Gas ($/mmBtu)	2.0*	-12.1	2.0	-12.3
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	195.2	10.5	319.2	9.9
Maize	190.6*	3.8	335.3	11.5
Sugar	398.5*	17.6	492.1	0.6
Palm oil	762.5	43.2	1,234.4	42.7
Rubber	1,573.5*	14.1	1,941.2	15.1
Coffee Robusta	1,285.0*	7.6	1,927.1	1.2
Cotton	1,569.0	9.5	1,642.5	1.7

* As on Jan 17, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.1& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	121.5	32941
Oil and Oilseeds	420.9	84196
Spices	0.8	9
Metal(Jan 16)		
Metal- non ferrous	6778.6	49245
Metal- precious	8447.7	412
Oil and gas(Jan 16)		
Gas	2496.3	58930
Oil	13459.8	1543

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	162.3	122194
Grains	175.2	97450
Oil and Oilseeds	864.3	498205
Others	110.5	66545
Pulses	89.2	27745
Spices	48.6	23477

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Cardamom (Feb 14)	4101.4	4.0
Crude Oil (Jan 17)	4165.0	1.6
Kapas (Apr 30)	1133.0	1.1
Cotton (Jan 31)	19850.0	1.0
Zinc (May 29)	186.0	0.8
Natural Gas (Jan 28)	152.3	0.7
Zinc Mini (Jan 31)	182.9	0.6
Losers (* % Change)		
Nickel (Jan 31)	1015.2	-3.3
Crude Palm Oil (Jan 31)	788.4	-1.8
Copper (Jan 31)	452.3	-0.7
Lead Mini (Jan 31)	151.8	-0.6
Gold Petal (Jan 31)	3956.0	0.0

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
CottonSeed Oil-Akola (Jan 20)	2104.0	2.0
Bajra (Jan 20)	2020.0	2.0
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1134.5	1.1
CastorSeed New-Disa (Jan 20)	4140.0	0.8
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6406.0	0.5
Jeera Unjha (Jan 20)	15850.0	0.3
Chana-Bikaner (Jan 20)	4470.0	0.2
Losers (* % Change)		
Moong-Mertacity (Jan 20)	7540.0	-3.4
Coriander-Kota (Jan 20)	6356.0	-1.6
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Jan 20)	904.6	-1.0
Soyabean Indore (Jan 20)	4202.0	-0.8
Barley Jaipur (Apr 20)	1721.0	-0.2

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19850.0	2.6
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	4101.4	1.9
Zinc Mumbai (May 29)	186.0	0.6
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	0.4
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1264.1	-9.2
Alumini-Mumbai (Jan 31)	140.5	-3.1
Nickel Mumbai (Jan 31)	1015.2	-2.5
Lead Min Mumbai (Jan 31)	151.8	-2.4
Lead Mum (May 29)	153.7	-1.2
Copper Mum (Jan 31)	452.3	-1.1
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	182.9	-1.1
Gold Petal-Mumbai (Jan 31)	3956.0	-1.0

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6406.0	4.1
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	801.4	3.6
Bajra-Jaipur (Jan 20)	2020.0	2.5
Bajra-Delhi (Jan 20)	2020.0	1.8
Paddy-Basmati-Karnal (Jan 20)	3227.0	0.8
Maize-Sangli (Jan 20)	2032.0	0.6
Discount over spot price (In %)		
Coriander-Kota (Jan 20)	6356.0	-7.8
Moong-Merta City (Jan 20)	7540.0	-3.6
Soy Bean Indore (Jan 20)	4202.0	-3.1
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Jan 20)	7211.0	-1.3
Jeera Unjha (Jan 20)	15850.0	-0.4

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai	
Aluminium utensil scrap /kg	109	(109)
Aluminium ingots /kg	147	(145)
Brass sheet cutting /kg	327	(327)
Brass utensil scraps/kg	312	(310)
Copper heavy scrap /kg	435	(435)
Copper utensil scraps/kg	406	(408)
Copper wire bar /kg	468	(468)
Lead ingots /kg	157	(157)
Nickel Cathodes /kg	1050	(1060)
Tin slabs /kg	1315	(1305)
Zinc slabs /kg	187	(185)
Source:Bombay Metal Exchange		
Cotton	**Mumbai**	
Bengal Deshi /Qtl	10264	(10264)
DCH - 32 /Qtl	11501	(11445)
Jaydhar /Qtl	9983	(9983)
Shankar- 6 /Qtl	11304	(11248)
Source:Cotton Association of India		
Oil	**Mumbai**	
Castor FSG /10kg	877	(878)
Castor Comm /10kg	867	(868)
Ricebran oil/10kg	820	(-)
Groundnut oil /10kg	1140	(1150)
Linseed oil /10kg	975	(-)
Karanji /10kg	800	(-)
Palm oil /10kg	865	(885)
Sunflower exp ref /10kg	915	(930)
Sunflower oil exp /10kg	890	(900)
Soyabean ref / 10kg	905	(920)
Source:Bombay Commodity Exchange		

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai	
Mumbai M-30 /Qtl	3412-3585	(3412-3585)
Source:Bombay Sugar Merchants Association		

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel		
NYSE Crude	58.83	(58.52)
Brent Crude (UK)	65.14	(64.82)
Brent Crude (WTI)	58.52	(58.52)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu (2.08)		2.04
Furnace/ 180 Cst &/bbl	323.36	(331.08)
Naptha spot /Rs/MT	45170	(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150	(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950	(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com		

सर्राफा

Gold	Mumbai	
Standard (99.50 Purity) /10 gms	39809	(39740)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	39969	(39900)
Silver.999/ kg	46555	(46270)
Source:India Bullion & Jewellers Association		

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	19460.45	19405.25
Alumini-Mumbai (M)	1 K	142.85	144.90
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2000.00	1985.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1963.65	1971.25
Barley Jaipur (N)	1 Q	2187.80	2187.80
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3950.00	4050.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4206.25	4197.00
Castor Seed-Kadi (N)	X	4125.00	4175.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4377.50	4377.50
Chana Delhi (N)	1 Q	4550.00	4534.15
Chana-Akola (N)	X	4375.00	4350.00
Coriander-Gondal (N)	X	6644.00	6633.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6825.00	6900.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6883.95	6895.80
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2100.00	2125.00
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2071.35	2097.60
Cotton-Kadi (N)	1 B	19301.90	19266.05
CPO-Kandla (M)	10 K	805.80	792.70
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	793.80	773.75
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	825.00	800.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	902.65	904.40
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1542.90	1547.35
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3432.75	3443.55
Gold Ahm (M)	10 G	39727.00	39804.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	31909.00	31971.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3990.00	3997.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7328.15	7303.60
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4014.70	4010.85
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4025.00	4025.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1130.20	1144.40
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	102.70	102.65
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16200.00	16200.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	15939.45	15909.10
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	900.20	896.90
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1050.60	1053.60
Kapas-Rajkot (N)	X	1062.30	1061.25
Lead Mum (M)	1 K	157.00	155.50
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1969.40	1970.65
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2376.00	2357.50
Maize-Erode (N)	X	2045.00	2045.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2260.00	2200.00
Maize-Sangli (N)	X	2030.00	2020.00
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4937.50	4900.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7700.00	7818.75
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4437.00	4462.75
Nickel Mumbai (M)	1 K	1055.80	1040.90
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3225.00	3200.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3214.00	3229.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	343.00	340.90
Pepper-Kochi (N)	1 Q	34500.00	34260.00
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	885.00	885.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	797.00	792.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1926.65	1931.95
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5180.40	5226.75
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	892.50	877.50
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	910.85	902.15
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	920.60	906.30
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	933.50	927.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13800.00	13800.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13800.00	13767.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46281.00	46527.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4350.00	4335.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4267.25	4279.90
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4393.50	4393.50
Soy Bean-Akola (N)	X	4293.00	4271.00
Soymeal Indore (N)	1 T	34500.00	34475.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	917.80	910.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	32320.00	32200.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	32310.00	32100.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	29560.00	29440.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3305.00	3287.50
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3404.60	3401.00
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3311.65	3324.10
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3490.50	3476.20
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3336.40	3340.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3166.10	3175.90
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6179.75	6152.50
Wheat Delhi (N)	1 Q	2350.00	2350.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2266.65	2255.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2300.00	2300.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2132.50	2177.50
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2350.00	2350.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5600.00	5700.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	6000.00	5975.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	186.50	184.80

* as on Jan 16, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

DAY SESSION

दिवस सत्र (शुक्रवार)

कृषि जिंस

Cotton

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19670, 19880, 19650, 19850	5791	881	18814
Feb 28	19940, 20160, 19910, 20140	4264	609	11565
Mar 31	20320, 20400, 20310, 20360	123	28	1722
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Jan 20	2080, 2115, 2080, 2104	600	34	3030
Feb 20	2076, 2136, 2067, 2133	53010	3417	95360
Mar 20	2101, 2162, 2093, 2156	8020	720	13450
Apr 20	2130, 2181, 2121, 2177	890	82	5540
May 20	2188, 2188, 2188, 2188	10	1	370
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1122, 1134, 1121, 1133	424	90	820
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1123, 1135, 1121.5, 1134.5	1341	726	4444

Grains

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Bajra NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	2020, 2020, 2020, 2020	20	2	130
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1721, 1721, 1721, 1721	10	1	1590
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4062, 4096, 4050, 4068	875	16	930
Feb 20	4096, 4164, 4064, 4150	38925	4361	89015
Mar 20	4136, 4202, 4110, 4192	2755	470	4545

Oil and Oilseeds

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4104, 4140, 4104, 4140	430	24	1135
Feb 20	4130, 4188, 4130, 4170	4520	486	26145
Mar 20	4160, 4274, 4152, 4206	810	107	7725
Apr 20	4188, 4212, 4188, 4210	55	8	3015
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	793.3, 802.4, 775.1, 788.4	24670	1812	36490
Feb 28	789, 797, 773.1, 784.9	24960	1559	38680
Mar 31	790.1, 790.1, 768.5, 778.6	1400	113	8500
Apr 30	762, 762, 761.8, 761.9	20	2	210
Mentha Oil MCX(1 K)				
Jan 31	1264.9, 1266, 1255, 1264.1	109.8	244	246.96
Feb 28	1272.7, 1275.5, 1264.5, 1274.5	44.64	99	67.68
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4350, 4350, 4300, 4330	90	8	1840
Feb 20	4296, 4328, 4268, 4310	12880	1039	12530
Apr 20	4309, 4330, 4265, 4309	7370	593	11090
May 20	4320, 4338, 4275, 4305	410	41	1430
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	909.8, 909.8, 898, 904.6	835	81	4730
Feb 20	890.2, 893, 871.2, 883	35920	3909	56845
Mar 20	880.4, 882.4, 865.2, 875.2	11895	1148	26875
Apr 20	870.6, 875, 860.6, 868.2	750	110	3200
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4250, 4250, 4178, 4202	1740	184	7950
Feb 20	4204, 4226, 4142, 4198	50930	5521	187545
Mar 20	4218, 4238, 4154, 4204	17005	2205	108900
Apr 20	4242, 4256, 4174, 4228	5005	742	34085
May 20	4250, 4272, 4190, 4208	835	126	3105

Others

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	7200, 7357, 7142, 7211	175	32	395
Feb 20	7260, 7430, 7216, 7411	12355	1997	56245
Mar 20	7369, 7525, 7320, 7511	2520	443	9905

Pulses

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4460, 4480, 4460, 4470	500	19	1050
Mar 20	4290, 4316, 4255, 4263	18770	1170	23480
Apr 20	4291, 4298, 4249, 4255	1370	122	2880
May 20	4294, 4294, 4275, 4288	190	17	230
Moong-Mertacity NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	7540, 7540, 7540, 7540	25	1	50

Spices

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	4062, 4101.4, 4062, 4101.4	2	16	7.1
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Jan 20	6450, 6470, 6301, 6356	1140	68	880
Apr 20	6980, 7100, 6874, 6951	3520	304	9450
May 20	6968, 7060, 6968, 6986	50	5	250
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	15850, 15850, 15850, 15850	12	4	72
Mar 20	15190, 15190, 15000, 15100	606	195	1755
Apr 20	14895, 14930, 14785, 14850	210	67	825
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6360, 6426, 6352, 6406	475	94	5555
Apr 20	6272, 6320, 6270, 6298	135	27	4600
May 20	6368, 6368, 6368, 6368	5	1	90

धातु

Metal- non ferrous

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jan 31	140.5, 141, 140.45, 140.8	2060	1450	4476
Feb 28	141.5, 141.9, 141.5, 141.7	283	198	1530
Copper MCX(1 K)				
Jan 31	452.25, 454.9, 452.25, 454.65	9437.5	3346	12507.5
Feb 28	454.5, 456.3, 454.05, 455.95	672.5	239	4450
Lead Mini MCX(1 K)				
Jan 31	152.05, 152.15, 151.45, 151.75	5326	3300	5703
Feb 28	152.7, 152.85, 152.35, 152.55	268	221	1299
Nickel MCX(1 K)				
Jan 31	1018.7, 1026.7, 1015.9, 1022.9	13113	7924	3382.5
Feb 28	1013, 1016.1, 1007.9, 1013.4	507	320	792
Mar 31	1012.5, 1012.5, 1012.5, 1012.5	1.5	1	4.5
Zinc MCX(1 K)				
May 29	187.4, 187.5, 184.6, 186.65	8	7	4
Zinc Mini MCX(1 K)				
Jan 31	182.95, 183.85, 182.8, 183.5	12776	7974	16701
Feb 28	183.05,

सीएए मामले में अदालत जाएगा पंजाब

केरल के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जहां नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित। केरल के राज्यपाल बोले, बगैर किसी सूचना के कानून के विरोध में अदालत जाने पर राज्य सरकार से मांग सकते हैं रिपोर्ट

पंजाब विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव के ध्वनिमत से पारित होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि केरल की तरह उनकी सरकार भी इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और विपक्ष शासित अन्य राज्यों में लागू करने के लिए केंद्र को सीएए में जरूरी संशोधन लाने पड़ेंगे।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब में जनगणना 2021 पुराने पैमानों पर ही होगी। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा जोड़े गए नए घटकों को इस जनगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को तीन घंटे की चर्चा के बाद पारित किया गया। केरल के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जहां नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रस्ताव का समर्थन किया, वहीं भाजपा ने इसका विरोध किया। वहीं शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने संशोधित कानून के तहत नागरिकता देने के लिए समुदायों की सूची में मुस्लिमों को शामिल करने की मांग की।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है

विभाजनकारी कानून

अमरिंदर सिंह ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है और दावा किया कि 1930 के दशक में एडोल्फ हिटलर ने जो जर्मनी में किया था वैसी ही कार्रवाई अब देश में हो रही है। इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कैप्टन अमरिंदर ने इस कानून को विभाजनकारी तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनपीआर) को हादसा करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में जो घटनाएं हो रही है वह उनके जीवनकाल में हो रही हैं।

नागरिकता संशोधन कानून 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है जबकि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को इससे बाहर रखा गया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संशोधित नागरिकता कानून को लेकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और कांग्रेस नेता को चुनौती दी कि इस कानून पर 10 वाक्य बोलकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि राहुल दो वाक्य में बता दें कि सीएए को लेकर उन्हें क्या दिक्कत है।

रिपोर्ट मांगेंगे राज्यपाल

केरल के राज्यपाल ने कहा है कि उन्हें सूचना दिए बिना नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को लेकर वह राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अदालत का दरवाजा खटखटाने पर वाम शासित राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि इस बारे में उन्हें सूचना नहीं देने को लेकर वह रिपोर्ट मांग सकते हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर प्रहार करते हुए खान ने कहा कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की सनक के अनुसार सरकार नहीं चलाई जा सकती और हर किसी को नियमों का सम्मान करना होगा।

केरल सरकार ने 13 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में कानून को चुनौती दी थी और इसे संविधान के प्रतिकूल घोषित करने की मांग की थी। खान ने कहा, 'जब भी मैं देखता हूं कि उल्लंघन हुआ है, वे नियमों से हट रहे हैं, संविधान के प्रावधानों से अलग होते हैं तब मैं निश्चित तौर पर रिपोर्ट मांगूंगा।' राज्यपाल ने कहा कि उन्हें सुनिश्चित करना है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल नहीं हो।

एनपीआर का जिक्र नहीं

केरल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 2021 की जनगणना पर परिपत्र भेजने के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का उल्लेख नहीं किया जाए। एक पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव के आर ज्योतिलाल ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत तौर पर इसे सुनिश्चित करें क्योंकि पिछले महीने राज्य सरकार ने राज्य में एनपीआर से संबंधित सभी मामलों पर रोक लगा दी थी। राज्य में 2021 में जनगणना अभियान के पहले चरण के साथ एनपीआर की भी प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। यह पत्र इसलिए जारी किया गया है क्योंकि सरकार के संज्ञान में आया था कि कुछ जनगणना अधिकारी 2021 जनगणना से संबंधित परिपत्र भेजने के दौरान एनपीआर अभियान का उल्लेख कर रहे हैं।

एजेंसियां

'सक्रिय राजनीति में अभी नहीं'

फोटो: दलीप कुमार

दिल्ली की जामा मस्जिद में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर

तिहाड़ जेल से रिहा होने के कुछ घंटे बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार को जामा मस्जिद पहुंचे। उन्होंने वहां संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। आजाद ने नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि देश को एकजुट रखने से ज्यादा महत्त्वपूर्ण कोई और चीज नहीं है। उन्हें गुरुवार की रात जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा किया गया।

उन्होंने शाहीन बाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और देश के अन्य हिस्सों में इस कानून के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए महिलाओं की तारीफ की। आजाद ने कहा, 'नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन देश के भविष्य, हमारी पहचान और संविधान बचाने के लिए है। इसे मजबूत करना हमारा दायित्व है।' उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी के बारे में वह बाद में फैसला लेंगे क्योंकि फिलहाल काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। ऐसी चर्चा थी कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। उन्होंने पिछले महीने सक्रिय राजनीति में उतरने की घोषणा की थी।

भाषा

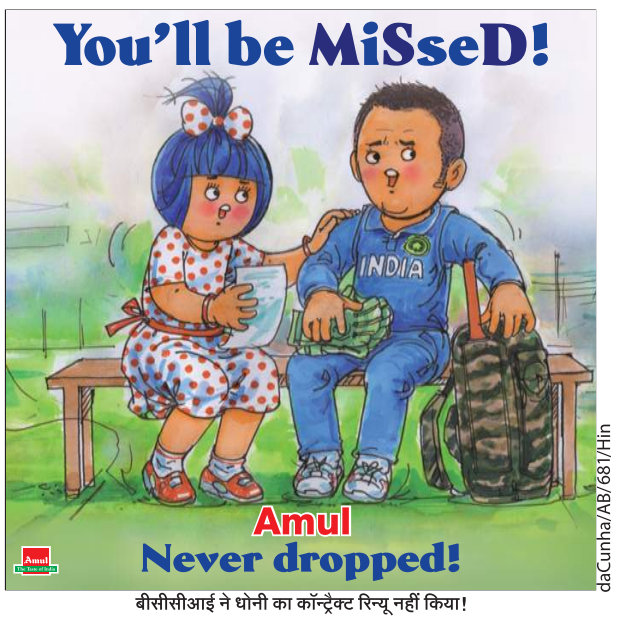

बीसीसीआई ने धोनी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया!

फ्रेंच गुयाना से जीसैट-30 का सफल प्रक्षेपण

टी ई नरसिम्हन

देश में प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के मकसद से भारत ने शुक्रवार को तड़के उच्च गुणवत्ता वाले संचार उपग्रह जीसैट 30 का दक्षिणी अमेरिकी के उत्तर-पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से सफल प्रक्षेपण किया। यूरोपीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एरियनस्पेस के एरियन 5 वीए-251 यान ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के जीसैट-30 और फ्रांस की दूरसंचार कंपनी यूटेलसैट के लिए यूटेलसैट कनेक्ट उपग्रह को भारतीय समयानुसार देर रात 2 बजकर 35 मिनट पर दक्षिण अमेरिका के उत्तरपूर्वी तट पर फ्रांसीसी क्षेत्र कौरू के एरियर प्रक्षेपण परिसर से प्रक्षेपित किया गया। करीब 38 मिनट 25 सेकंड की उड़ान के बाद जीसैट-30 एरियन 5 से अलग होकर दीर्घवृत्ताकार भूस्थिर अंतरण कक्षा में स्थापित हो गया।

इसरो के अध्यक्ष के शिवन ने एक बयान में कहा, 'यह उपग्रह केयू बैंड के जरिये देश की मुख्य भूमि और द्वीपों को संचार सेवाएं मुहैया कराएगा और सी बैंड के जरिये खाड़ी देशों और बड़ी संख्या में एशियाई देशों तथा आस्ट्रेलिया को व्यापक कवरेज देगा।' उन्होंने बताया कि जीसैट-30 डीटीएच टेलीविजन सेवाएं मुहैया कराने के साथ ही एटीएम, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीविजन अपलिंकिंग और टेलीपोर्ट सेवाएं, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज संग्रह (डीएसएनजी) तथा ई-गवर्नेंस ऐप्लिकेशन को वीसैट से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। इसरो ने कहा कि कर्नाटक के हासन में इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी (एमसीएफ) ने जीसैट 30 के प्रक्षेपण यान से अलग होने के तत्काल बाद कमान और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और उपग्रह की शुरुआती जांच के अनुसार यह पूरी तरह ठीक है। आने वाले दिनों दिनों में उपग्रह की संचालक शक्ति वाली प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए कक्षा को बढ़ाया जाएगा ताकि इसे भूमध्य रेखा के 36,000 किमी ऊपर भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया जा सके। इसरो ने कहा कि कक्षा बढ़ाने के अभियान के अंतिम चरण में जीसैट 30 पर दो सौर सारणी और एंटीना रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। कक्षा में सभी परीक्षणों के सफल होने के बाद उपग्रह अपना काम शुरू कर देगा।

- एरियनस्पेस के एरियन 5 वीए-251 यान से किया गया प्रक्षेपण
- जीसैट-30 के अलावा यूटेलसैट कनेक्ट उपग्रह का भी हुआ प्रक्षेपण
- जीसैट-30 केयू बैंड से देश की मुख्य भूमि और द्वीपों को संचार सेवाएं देगा
- सी बैंड के जरिये खाड़ी देशों और एशियाई देशों को कवर करेगा

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसा बन सकता है वडाला

पवन लाल

एक दौर में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) नया और अच्छी तरह डिजाइन किए गए व्यावसायिक जिले की मिसाल बना था। लेकिन अब वहां जमीन की कमी दिखती है और यह इलाका काफी बंद सा दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि अब वडाला भविष्य के बीकेसी के तौर पर उभर रहा है।

राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के अध्यक्ष और हीरानंदानी समूह के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि बीकेसी शैली का जिला बनने की वडाला में पूरी संभावना है भले ही यह एक छोटे पैमाने पर हो सकता है। उनका कहना है कि बीकेसी की तुलना में विकास के लिए जितनी मात्रा में जमीन मौजूद है वह सीमित है।

उनका कहना है, 'मुंबई क्षेत्र के अन्य विकसित जिले की तरह ही यह क्षेत्र है जिनमें नवी मुंबई और पवई शामिल है।' उनका कहना है, 'वडाला की कनेक्टिविटी और बीकेसी के साथ इसके लोकेशन के लिहाज से एक अलग ही फायदा है। वडाला के नागरिकों के लिए नया सायन -बीकेसी फ्लाइओवर खुला है।'

लोढ़ा समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शैशव धरिया का कहना है कि इस क्षेत्र में कंपनी की 22 एकड़ जमीन है और उनका कहना है कि सायन-बीकेसी पुल खुलने का मतलब यह हुआ कि वडाला से बीकेसी (जी ब्लॉक) पहुंचने में कार से 10 मिनट से भी कम समय लग सकता है।

उनका कहना है, 'इसका अर्थ यह हुआ कि वडाला बीकेसी का अच्छा विस्तार है (यहां कुर्ला या कलानगर जाने के मुकाबले कम समय लग सकता है) और इसी वजह से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) इसे बीकेसी-2 कहता है। इसके अलावा वडाला के अपने सामाजिक बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहे हैं ऐसे में यहां के निवासी और ऑफिस यूजर भी बीकेसी में बन रहे मॉल और कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। इसका भी बड़ा फायदा है।'

इस क्षेत्र की दूसरी रियल एस्टेट कंपनियों में अजमेरा रियल्टी ऐंड इन्फ्रा इंडिया भी शामिल है। लंबे समय में वडाला क्षेत्र की सफलता में बीकेसी से नजदीकी अपने आप में एक अहम कारक है। संपत्ति प्रबंधन कंपनी जेएलएल इंडिया के सीईओ और कंट्री प्रमुख रमेश नायर कहते हैं, 'दफ्तर के लिए जगह मुहैया कराने के लिहाज से बीकेसी की अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है। ऐसे में सबसे नजदीकी विकल्प वडाला है। बीकेसी में काम कर रहे लोगों के लिए प्रमुख आवासीय विकल्प बेहद कम है और वडाला इस खालीपन को भरता है।'

बीकेसी शैली का व्यावसायिक जिला बनने की वडाला में पूरी है संभावना

कैसी है दर

धारिया का कहना है कि लोढ़ा न्यू कफ परेड प्रोजेक्ट के तहत कंपनियों और आवासीय खरीदारों के लिए बनी ग्रेड-ए बीकेसी इमारतों के लिए दफ्तर और आवासीय दर करीब 50-60 फीसदी के स्तर पर है। मिसाल के तौर पर लोढा एक्सेलस बिल्डिंग में दफ्तर की मौजूदा दर करीब 140-150 रुपये प्रति वर्गफुट है जो बीकेसी में 275-325 रुपये है। वडाला की एक खास बात यह भी है कि इसकी नजदीकी इस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे (ईईएच), मोनोरेल और आने वाले मेट्रो 4 कॉरिडोर से है। इसके अलावा एमएमआरडीए ने हाल में वडाला को बीकेसी-2 में बदलने की योजना की पुष्टि की है जो बीकेसी की तर्ज वाला एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। धरिया का कहना है, 'वडाला, चेंबूर और शिवड़ी ऐसे इलाके हैं जहां मुंबई में काम करने वालों की तादाद बढ़ रही है और ये इलाके बीकेसी-ईईएच पुल से अच्छी तरह जुड़ते हैं और यह बीकेसी को दक्षिण मुंबई से जोड़ेगा।' अब तक लोढ़ा ने न्यू कफ परेड परियोजना के 1,800 फ्लैट लोगों को दिए हैं जिसमें 1500 लोग रह रहे हैं और अगले कुछ सालों में दूसरा टावर भी तैयार हो जाएगा।

वडाला और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए फ्लाईओवर एक सकारात्मक कदम है और इससे इस जिले में काफी चहल-पहल रहेगी। अस्पताल और स्कूलों जैसा बुनियादी ढांचा शुरुआत में सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। वडाला चेंबूर और माटुंगा से नजदीक है और यहां के निवासी स्कूल और अस्पताल के लिए यहां जाते हैं। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि एमएमआरडीए द्वारा जारी बड़ी योजना की तर्ज पर ऐसा कोई बुनियादी ढांचा न तैयार हो जाए।

रियल्टी कंसल्टेंसी और प्रबंधन कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया में कार्यकारी निदेशक गुलाम जिया ने बताया कि ट्रांस-हार्बर लिंक का काम प्रगति पर है और बांद्रा-वर्ली सीलिंक से जोड़ने की तैयारी भी है। वडाला भी बीकेसी के मुकाबले में व्यावसायिक कारोबारी जिले का तमगा हासिल करने के लिए तैयार है। वह कहते हैं कि करीब एक दशक में वडाला मुंबई का केंद्रीय कारोबारी जिले के तौर पर उभरेगा।

सामाजिक उद्यमियों को भाता देश

श्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के साथ काम करने करने सामाजिक उद्यमियों ने कर्ज या उत्पाद मूल्य और सेवाओं के रूप में 6.7 अरब डॉलर का योगदान दिया है जिससे 190 देशों के 6.2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी में सुधार आया है। शुक्रवार को जारी एक अध्ययन के मुताबिक भारत में सामजिक उद्यमियों की मौजूदगी के लिहाज से शीर्ष स्तर पर है। इन सामाजिक उद्यमियों ने 19.2 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करने और 22.6 करोड़ बच्चों व युवाओं की शिक्षा में सुधार के लिए काम किया है।

इसने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों तक ऊर्जा पहुंचाने और 2.5 करोड़ लोगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने की कवायद की। 50वें विश्व आर्थिक मंच के दावोस में होने वाले सालाना सम्मेलन से पहले 'दो डिकेड्स ऑफ इम्पैक्ट: श्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप' शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई जिसका जोर इस बात पर है कि सामाजिक उद्यमी कैसे व्यवस्था में बदलाव का कारक बने और सतत विकास में अपना योगदान दें।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'उन परियोजनाओं और उत्पादों पर 6.7 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किया गया है जिससे लोगों की आजीविका बढ़ाने और लोगों तक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बनाने, स्वच्छ ऊर्जा देने और शिक्षा में सुधार जैसी कोशिशों को अंजाम दिया जा सकता है।'

एजेंसियां

खेल और समाचार चैनलों के लिए ज्यादा खर्च को तैयार दर्शक

बार्क के आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 में नए टैरिफ ऑर्डर आने के बाद भी दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और दर्शक खेल तथा समाचार चैनलों को बहुतायत में देख रहे हैं

सोहिनी दास

वर्ष 2019 में नए टैरिफ ऑर्डर (एनटीओ) आने के बाद भी टेलीविजन दर्शकों की संख्या में अच्छी तेजी देखी गई। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के आंकड़े यह बताते हैं। इसमें भी खासकर समाचार तथा स्पोर्ट्स चैनलों के दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ी। उद्योग सूत्रों का कहना है कि नए साल में टी20 विश्वकप, दिल्ली चुनाव तथा राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनपीआर) जैसे विषयों के चलते यह चलन बरकरार रहेगा।

बार्क इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) रोमिल रामगढ़िया कहते हैं, 'साल 2019 में इंडियन प्रीमियर लीग और क्रिकेट विश्व कप जैसे बड़े आयोजन देखे गए। इसके अलावा आम चुनाव, पुलवामा हमला तथा अनुच्छेद 370 को हटाया जाना जैसे विषय सुर्खियों में रहे।' उनका कहना है कि एनटीओ के आने के बावजूद आईपीएल के दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। बिग बॉस तथा कौन बनेगा करोड़पति के दर्शकों की संख्या भी बढ़ी। प्रत्येक वर्ष मार्च से मई के बीच आईपीएल का आयोजन होता है और इस बार 12वें संस्करण के समय ही एनटीओ भी लागू किए गए। हालांकि इसके बावजूद दर्शकों की संख्या में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

बार्क के आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 के आईपीएल में दर्शकों के 14.2 अरब इम्प्रैशन दर्ज हुए तो वहीं 2019 में 15.8 अरब इम्प्रैशन दर्ज हुए। इसी तरह प्रमुख कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या में भी तेजी देखी गई। पुलवामा तथा बालाकोट हमले के दौरान 4.9 अरब व्यूअरशिप दर्ज की गई जो आम चुनाव के दौरान दर्ज 4.8 अरब से भी अधिक है। रामगढ़िया कहते हैं, 'नए टैरिफ ऑर्डर तथा कीमतों में बदलाव के बाद भी 2019 में इस तरह की घटनाओं के लिए दर्शकों की संख्या में तेजी दर्ज की गई।' सालाना आधार पर केबीसी तथा बिग बॉस के दर्शकों की संख्या में क्रमश: 9 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। खेल, समाचार तथा बड़ी घटनाओं के अलावा दर्शकों ने रोजाना के लिए मनोरंजन की ओर भी रुख किया।

घटना	2019 में समय (सप्ताह)	इम्प्रैशन (अरब में)
पुलवामा तथा बालाकोट हमला	9	4.9
आम चुनाव	21	4.8
अनुच्छेद 370	32	3.4

बार्क का कहना है कि दर्शकों ने 4-5 मनोरंजन चैनलों के स्थान पपर 2-3 मनोरंजन चैनलों पर ही टिके रहे और वर्ष 2020 में भी यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। रामगढ़िया बताते हैं, 'सबस्क्राइब किए गए चैनलों पर लोगों ने अधिक समय बिताया है जो विज्ञापनदाताओं तथा प्रसारकों के लिए अच्छा है। यह दिखाता है कि उनके पास वफादार दर्शक हैं। हालांकि चैनलों की संख्या में गिरावट आई है।' प्रसारक स्वीकार करते हैं कि पिछले साल एनटीओ के लागू होने के बाद से 1.2-1.5 करोड़ ग्राहकों का नुकसान हुआ है। साथ ही, विशेषज्ञ कहते हैं कि टैरिफ में बदलाव के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जाना चाहिए जो एक बड़ा काम है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्याधिकारी एन पी सिंह कहते हैं कि उपभोक्ताओं को कीमतों में बदलाव के बारे में जागरुक करने की कुल लागत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है। हालांकि जागरुकता तथा नए टैरिफ अपनाए जाने की दर इसकी जटिल प्रवृति के बाद भी काफी अधिक है।

वायोकॉम18 के मुख्य कार्याधिकारी तथा प्रबंध निदेशक एवं आईबीएफ के उपाध्यक्ष सुधांशु वत्स कहते हैं कि करीब 94 प्रतिशत भारतीय एनटीओ के बारे में जानते हैं। वह कहते हैं, 'मासिक आधार पर आंकड़े बताते हैं कि लोग अपनी पसंदीदा चैनल की कीमतों को लेकर सशंकित रहते हैं।' हालांकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने फिलहाल फरवरी 2019 के टैरिफ ऑर्डर में संशोधन किया है। लेकिन प्रसारक टैरिफ में लगातार बदलाव से परेशान हैं और संशोधनों पर रोक लगाने के लिए अदालत जाने की योजना बना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नियामक तथा प्रसारकों के बीच इस लड़ाई से दर्शकों की संख्या तथा प्रवृति पर असर पड़ेगा।

मुंबई स्थित एक विश्लेषक ने कहा, 'ग्राहकों ने नए टैरिफ नियमों को अपना लिया जिससे उसका बहुत अधिक असर नहीं दिखा। हालांकि नए संशोधनों से सामग्री निर्माण के साथ साथ छोटे चैनलों पर भी प्रभाव पड़ेगा।'